साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 94795 35569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 10 प्रति सोमवार इंदौर, 9 से 15 अक्टूबर 2023 पृष्ठ 12 मूल्य 5/- रुपए

विश्व घातक संगठन (WHO) स्वास्थ्य के नाम डराओ लूटो

अमेरिकी और चीनी कंपनियों ने विश्व को बर्बाद करके कमाया लगभग रु. 50 लाख करोड

(समय माया)

विश्व घातक संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर अब नए षड्यंत्र निपाह वायरस की मार्केटिंग और उसके लिए बनाए जा रहे टीके के अंतर्गत प्रसार माध्यमों इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से भय फैला कर मोटी कमाई की नई चालों की तैयारी में लगा हुआ है। वैसे भी उसका अध्यक्ष टेंट हाउस बेचारा मात्र एमएससी पास अफ्रीका के देश का है जिसे यह हरामखोर जल शास्त्र डकैती डालने वाली सरकारों को खरीद कर नचाने वाली वॉलमार्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी उपभोक्ता सामग्री और तक बनाने वाली मॉडर्ना फाइजर वह अन्य सैकड़ो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसको टुकड़े डालकर अपने तरीके से नीचा कर दुनिया की जनता की को भ्रमित करअपनी लूट का तांडव करती रहती है। जैसा कि विश्व घातक संगठन का पिछले 70 सालों का इतिहास है।

सारे एलोपैथिक डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च सब के सब इन घोर नीच अमेरिकी दवा उत्पादक कंपनियां के चांडालों के जालसाज गिरोह के विश्व व्यापी धन बांट सरकारों को खरीद अपने माल बेंचने व शर्ते थोप जनता को बीमारी के नाम डरा धमका डायबिटीज बीपी एड्स हेपेटाइटिस स्वाइन फ्लू, हृदय यकृत प्लीहा कोरोना के मास्क ऑक्सीजन व अन्य सामग्री, हजारों करोड़ के टीके बेचने और कमाई करने के लिए भ्रमित करने वाले संगठन के एजेंट है। भारत में।

आइएमए, आईसीएमआर मानता है, की स्कूलों में बच्चों को अनावश्यक जबरदस्ती टीके ठोकने से करोड़ों बच्चों और युवाओं की अकाल मौत हो रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना माल मोबाइल बेचने इंटरनेट का उपयोग करने कोरोना की आड़ में ऑनलाइन पढ़ाई का जो तांडव का षड़यंत्र किया। बच्चों को पढ़ाई की और मैं मोबाइल पकड़ा कर उसकी आदत डलवा अपना माल ऑनलाइन बैचने का षड्यंत्र कर बच्चों की नींद पढ़ाई दिमाग आंखें और शरीर कमजोर कर बर्बाद कर औषधियां इयरफोन चश्मे बीपी डायबिटीज बेचने का षड़यंत्रों का तांडव कर रहे हैं। उससे बच्चों का बचपन छीनने शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर कर सोचने की क्षमता खत्म कर युवाओं को दवाओं पर जीवन निर्भर कर भारत के आगे बढ़ने, **(शेष पेज 10 पर)**

दुनिया का सबसे बड़ा शैतान डकैत अमेरिका

रूस-यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा घी बर्बाद हो रहा यूरोप खाड़ी देश

(समय माया)

दुनिया में युद्ध कहीं पर भी हो असर विश्व के पर्यावरण व सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं और फसल चक्र पर भी पड़ता है। जिससे हर देश में गरीब और गरीब होते हैं बेरोजगारी भूख कुपोषण बढ़ता है अमेरिका की दुनिया में सबसे ज्यादा षड्यंत्रों युद्ध जो उसकी अर्थव्यवस्था के आधार हैं करवाने में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने दादागिरी ठोकने अरुण वाडकर गुलाम बनाने के मंसूबे पालता है। उसकी अगाती पिछली एक शताब्दी से ज्यादा समय से चली आ रही है यह पूंजीवादी राष्ट्र उसकी चांडाल लुटेरे कंपनियां अपना व्यवसाय कर मोटी कमाई करते हैं। उसके बने सभी संगठन यूएन ओ अर्थात विश्व शैतान संघ वह उसके अन्य सहयोगी संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड टेरिफिक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात वर्ल्ड हैजर्डस ऑर्गेनाइजेशन आदि सभी संगठनों का कामदुनिया पर अपनी शर्त लाद कर दुनिया को अपनी तरीके से हांकने व गुलाम बनाने का षड्यंत्र करते हैं। उसका नाटो यूरोप के बड़े गुंडे अमेरिकाने डरा धमका कर छोटे राष्ट्रों को अपने साथ मिलकर दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए और गुंडागर्दी ठोकने के लिए नौटंकी करने का षड्यंत्र पिछले 50 साल से ज्यादा समय से कर रहा है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को भड़काने उसमें लगातार अपने सारे कबाड़ा हथियार मिसाइल युद्धक विमान जहाज उसको देकर लगातार चलवा रहा है। आखिर दुनिया में जो वर्तमान युद्ध

रूस और यूक्रेन का चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन उसके लिए वही संकर प्रजाति के घोर धूर्त अमेरिकी सरकार को चलाने वाली हथियार गोला बारूद मिसाइल उत्पादक कंपनियां है। जिनका उद्देश्य अपने स्वार्थ की और माल बेचने की खातिर दुनिया में जंग लड़वाते रहना है। ताकि एक तरफ उनका माल बिकता रहे दूसरी तरफ लड़ने वाले देश आपस में कमजोर होकर उनके गुलाम बनाने की षड़यंत्रों में लपेटे में आते रहें।

(शेष पेज 7 पर)

पिछले 18 साल में 18 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले

जाना निश्चित, तो क्यों लगे हो मप्र की बर्बादी में

(समय माया)

2006 से घोर भ्रष्ट जालसाज डकैत शिवराज ने कुछ महत्वपूर्ण विभागों की ही बात करें जिसमें लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, मप्र जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, शहरीय विकास, ग्रामीण विकास, वन विभाग, खनिज, गृह, ऊर्जा, आदिम, अनुसूचित जनजाति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वाणिज्य कर जिसमें शराब पंजीयन आदि भी आते हैं, बस इन विभागों में मात्र 1000 से 10000 करोड़ हर

भोली सूरत देहाती अंदाज करते रहे चारों तरफ बर्बादी का आगाज

विभाग का औसत भी निकले तो तो 18 लाख करोड़ बहुत कम होते हैं। जबकि खनन में तो लगातार निरंतर 24 घंटे खनन चलता रहा और 700 डंपर रेती पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र तक में बैंचते रहे। उसके सिंहस्थ की खरीदी और सेवाओं की भुगतान के नाम का घोटाला जो 20000 करोड रुपए से ज्यादा का था। कोरोना के समय लगभग 1 लाख करोड रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार जनता के भोजन पानी दवाई स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर दिखाकर हजम कर लिया गया यथार्थ में हजारों करोड़ के तोप्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कैंप ऑक्सीजन प्लांट लाइन आदि के कागजों पर निर्माण में हजम कर लिया गया। बस अभी जमीनों की खरीदी बिक्री भू और कॉलोनी माफियाओं, के साथ मिलकर नजुल की, रेवेन्यू, चरनोई सरकारी विभागों की **(शेष पेज 8 पर)**

घोर पाखंडी सत्ताधीश अपनी नाकामी छुपाने जनता को भ्रमित करने ऐसे षड्यंत्र रचते हैं

चंद्रमा पर यान पूर्णतः बकवास

भारत का चंद्रमा पर यान उतारना-सत्ताधीशो की पूर्ण नौटंकी, जन धन की बर्बादी

(समय माया)

अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 भी कभी चंद्रमा पर नहीं उतरा था। आज तक वह भी बकवास झूठ जो है बार बार छाप कर सच करके बताया जा रहा है। जबकि वह दुनिया पर अपना झूठा रतवा पेलने पूरी गप्प व बकवास है। ऐसी अनेकों हरकतें उन्नीस सौ से अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली बनाने बताने शक्ति प्रदर्शन का झूठा प्रपंच करने का षड्यंत्र करता रहा है। अमेरिका 1956 से लेकर 1975 तक वियतनाम से युद्ध में बुरी तरह से पिटता रहा। उसकी एक इस नाकामी नहीं पूरी दुनिया में उसकी थू थू करवा दी। पूरी दुनिया में उसे बहुत कमजोर और फांकू समझा जाने लगा। अपनी उस नाकामी को छूपाने दुनिया में अपने को महानतम वैज्ञानिक रूप से समृद्ध राष्ट्र सिद्ध करने के लिए चंद्रमा पर आर्मस्ट्रांग को उतारने कानाटक किया था। पिछले 54 सालों से अमेरिका मूर्ख बना रहा था। अब उसमें भारत भी शामिल हो गया। यह केवल दुनिया

की जनता को अपनी फर्जी उपलब्धियों को गिनाने का षडयंत्र कारी तरीका है। रूस ने कभी नही कहा- वह चंद्रमा के निकट या उसके करीब पहुँचा। इस सच्चाई की पोल सन 2002 में मैंने खोल दी थी। जब मैं अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहा था ऊपर से क्लब का 2 सीटर जहाज गुजरा। सीधी सी बात थी। दिमाग में खुजली हुई अपने जहाज न उड़ा पाने के कारण। तो अचानक मस्तिष्क में अपने द्वारा पढ़ी हुई हवाई जहाज से संबंधित किताबों को की हवाई जहाज पृथ्वी के वातावरण में हवा पर तैरता है। तो अमेरिका पिछले 54 सालों से दुनिया की जनता को यह कहकर क्यों मूर्ख बना रहा है कि वह चंद्रमा पर उतरा। **(शेष पेज 9 पर)**

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

हिन्दूओं के संरक्षक पाखंडी भक्षक

हिन्दूओं के संरक्षक होने का पाखंड करने वाले संगठनों, राक्षस सेवा संघ भुखेरा जन पार्टी व उसकेआईटी सेल के जनधन से पाले हुए अंध भक्तों जाहिल आपराधिक मानसिकता के घोर स्वार्थी मोदी ने 9 साल में सबसे ज्यादा बर्बादी हिंदुओं की। 14-15 में, चीन अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कं. व अपने पूंजीपति मित्रों के मोटे फायदे और शॉपिंग मॉल चलाने जिसमें सफाई में 10 करोड़ से ज्यादा पूरे देश के ठेले वाले पगमार्गो वाले छोटी दुकानदार गुमटियां सब साफ कर दिए गए। उससे जो बचे कैशलेस में निपटाये, नोटबंदी के 4 महीने तक 40 करोड लोग बेरोजगार कर दिये जीएसटी मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स की छूट देकर देश के 20 करोड़ से ज्यादा उद्योग, छोटे व्यापारी दुकानदारों को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अंध भक्तों तुम्हारे परिवार के भी अनेकों लोग फर्जी बीमारी कोरोना के डर से में मरे होंगे और कुल 5 करोड़ हिंदुओं की मौत के बाद टीके से 5 करोड़ तो टीका लगने के 3 महीने में ही मौत के बाद भी टपकते हुए युवा बच्चों बूढोकी मौत नहीं दिखी रही है हरामखोरों को,टीके से मरने वाले अभी भी मर रहे हैं। 1989 में कश्मीर में हिंदुओं का, 2002 में गोधरा में, 44 पुलवामा में कत्लेआम करने वाला तुम्हारा मोदी ही था ना। कितनी नीच छिछोरी गिरवी मानसिकता के लोग हैं। वह मौत का जश्न मना रहा है और यह उसके गुण गा रहे हैं। इन सब अंध भक्तों को भी अकाल मौत दे जिन्होंने टीका लगवा लिया हो जो बचेंगे वह अपनी जंग लड़ लेंगे। इन सबसे सहस्त्रों वर्षों की गुलाम मानसिकता के सत्ता के तलवे चाटने वाले मूर्खों नालायकों के दम पर हिंदुओं की जंग नहीं लड़ पाएगा इन्हें तो बस चुनाव में उसकी सत्ता का मुफ्त का माल चाहिए। नोबेल पुरस्कार पाने, दुनिया में शांति का महादूत सिद्ध करने यह पाखंडी चांडाल राक्षस चुनाव जीतने हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के लिए कितना बेताब है। यह अंध भक्तों के भड़काने संदेशों से सिद्ध होता है। पिछले 9 सालों में देश में एक करोड़ से ज्यादा रोहिंग्याओं को दिल्ली में किसने बसवाया, गृह मंत्री अमित शाह ने इनके कार्यकाल में आए कितने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, रोहिंग्या मुस्लिमों को बाहर किया? रोहिंग्याओं को तो उल्टे ही मुफ्त मकान दिए? इंदौर का जालसाज, सिंधी सांसद लालवानीपाकिस्तानी मुसलमानों जो सिंधी व हिंदू बना कर लाखों रुपए लेकर भारत मैं बसवा रहे हैं। अरबों रुपए की मोटी कमाई कर खुलकर मध्यप्रदेश में व देश में बसवा रहा है। यह अंध भक्तों को सब कुछ जानने के बाद में कभी इन सब षड्यंत्रों पर ऊपर उंगली उठाई। उल्टे ही अपनी उंगलियों को अगाडू पिछाडू फंसा कर, आईटी सेल की आवाज में भ्रमित कर हिंदुओं की बर्बादी में लगे हो सूअर के पिल्लों, इससे तुम तुम्हारा परिवार समाज पूरी बर्बाद हो रही है समझ में आया। अगर सच्चे अंधभक्त हो तो टीका लगवाया ही होगा अपनी अकाल मृत्यु का इंतजार करो। वैसे प्रभु से प्रार्थना है कि उससे पहले आप अपने घर परिवार के वह जीवन के सोचे हुए और जो अच्छे काम हो वह पूरे कर लो। फिर लहर लाने की तैयारी में है। बचे कुचे उसमें साफ हो जाओगे। वह भेड़िए मोदी ने 1989 में पहले कश्मीर में मुसलमानों के साथ मिलकर लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, पलायन करवाया और पूरा कश्मीर खाली करवा दिया। फिर हिंदुओं को डराने धमकाने भय पैदा करने गोधरा कांड में मस्जिद तोड़ने लेकर गए हजारों राम भक्तों को जिंदा डिब्बों में आग लगवा कर नरसंहार करवाया। फिर 9 साल में हिंदुओं की गजब बर्बादी की। सफाई, कैशलेस, नोटबंदी, जीएसटी मैं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर भूख से मारा। 10 करोड हिंदू तो उसने केवल कोरोना के नाम मार डाले। जिसमें 5 करोड से ज्यादा 24 घंटे टीवी मोबाइल समाचार पत्रों कचरे की गाड़ियों तक से दहशत बांटकर, और 5करोड़ लोगों को जबरदस्ती स्कूलों मंदिरों बाजारो गली मोहल्लों में डरा धमका कर टीका लगाकर मरवा डाला और अभी भी किशोर उम्र के जवान बच्चे तक कीड़े मकोड़ों की तरह टपक रहे हैं। फिर श्रीराम मंदिर में हिंदूओं से इकट्ठा किया हुआ रु 30 हजार करोड़ से ज्यादा का धन सोना चांदी ईंटें आदि सब हजम, बाद में सरकारी पैसे से, काशीनाथ कारी डोर में सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ 1200 मंदिर तोड़े, लाखों साल पुरानी जीवित पवित्र पावन नगरी को, पर्यटन की डकैती नगरी में बदल, दर्शन के भी ?500 वसूल किए जाने लगे और आम हिंदुओं को दर्शन से भी वंचित कर दिया गया। अब धर्मशालायें नहीं अब पर्यटकों के लिए आम बनारस वासी भी अपने घरों को किराए पर देने की अपेक्षा होम स्टे फ्रंट बनाने लगे। वही हाल उज्जैन में महाकाल कारीडोर में भारी सैंकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार कर प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई। चारों तरफ के हजारों वर्ष पुराने छोटे-मोटे मंदिरों समाधियों को छोटे-मोटे दुकानों मकानों निर्माण तोड़ फोड़ साफ कर दिया गया। सीधे दर्शन के रु 500 लगने लगे। वही हाल ओंकारेश्वर सलकनपुर के मंदिरों का किया जाकर वहां पर भी हम हिंदुओं को दर्शन के नाम लूटने डकैती डालने का षड़यंत्र किया जा रहा है। हरामखोर अंधभक्त इस हिंदुओं की चारों तरफ बर्बादी करने वाले को लिए वरदान मानते हैं। गुलाम डरपोक जाहिल अंध भक्तों।

म प्र वन विभाग : भारतीय वन लूटो खाओ सेवा

कब तक षड्यंत्र करोगे, भ्रष्टाचार डकैती छुपाने

वन बाप की जागीर नहीं, जो सूचना के अधिकार में जानकारी की अपेक्षा बहाने

(समय माया)

मध्य प्रदेश वन विभाग में बैठे भारतीय वन लूटो खाओ सेवा के अधिकारी जो एसडीओ से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक पद पर बैठे हुए हैं। घोर भ्रष्ट जालसाज, वनों की भूमि, वन उपज, फसलें, खनिज पशु पक्षी वन प्राणियों के नाम पर भी हजारों करोड़ घोटाले करते हैं। मुख्य प्रधान वन संरक्षक वन्य प्राणी जिसे विश्व वन्य निधि से हर वर्ष 2000 करोड डालर अर्थात 170000 करोड़ रुपए वन प्राणियों के संरक्षण के लिए मिलता है वह सारा धन ऊपर के ऊपर हजम कर लिया जाता है दूसरी तरफ 1991 से अभी तक अर्थात 32 साल बाद भी जो डायरेक्टरी जिसमें 927 शेर और 1851 तेंदुए दिखाए गए थेआज भी वही चल रहे हैं ताकि विश्व वन्य अपनी निधि का रू.170000 करोड आसानी से हजम किया जा सके जबकि स्वयं मध्य प्रदेश सरकार का वन मंत्रालय मानता है की 300 से ज्यादा शेर व 550 से ज्यादा तेंदूए नहीं है पर उनके नाम पर मोटा पैसा वन मंत्री से मुख्यमंत्री तक हजम किया जा रहा है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर यहां बैठे सीसीएफ, डीएफओ एक तरफ हरामखोरों की फौज लिखती हैएक बिंदु से ज्यादा की जानकारी नहीं दी जाएगी तो वनेले सूकरों 18 साल सेधारा 4 के 17 बिंदुओं की और बाद में आठ आठ बिंदुओं की कुल 25 बिंदुओं की जानकारी को स्वयं स्वयं अपनी सीटों पर क्यों नहीं डाला जाता जबकि वह तो सार्वजनिक रूप से स्वयं ही मंत्रालय और विभाग को12 अक्टूबर 2005 से ही अपलोड कर देनी चाहिए थी ताकि उससे संबंधित कोई भी जानकारी किसी आवेदक को मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती पर भ्रष्टाचार का आलम यह है की एक-एक अधिकारी के पास दो-दो मुख्य संरक्षक के पद भार हैं। वैसे भी पिछले 8 सालों सेहर विभाग में मोटा धन लेकर एक ही अधिकारी को वरिष्ठ प्रभार 1-1, 2-2, 3-3 पद दिए जा रहे हैं।

इंदौर में बैठा नरेंद्र कुमार सनोड़िया जिसके पास सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लगभग 8-10 नर्सरींयां हैं उसमें भी माल बीज खरीदी के, नर्सरियों के रखरखाव में भी लाखों रुपए के पाइप बिछाने, सिंचाई के फव्वारे लगाने कैनोपी भवन निर्माण साथ-साथ मजदूरी भुगतान के साथ उन सभी नर्सरींयों में वहां बैठे हुए एसडीओ कार्यालय में बैठकर ही सबकी निरीक्षण रिपोर्ट भरते और पेट्रोल डीजल में भी पैसा हजम करते रहते हैं। दूसरी तरफ सनोड़िया के पास में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 संभागों का प्रभार भी है। जहां पर पूरे वर्ष भर वृक्षारोपण बनी प्राणी संरक्षण तेंदूपत्ता मजदूरों के पानी पिलाने वनों में रास्ते बनाने आदि में भ्रष्टाचार किया ही जाता है। स्वाभाविक है चार संभागों में वन उपज, वन अपराध, वन भूमि अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई, वन भूमि के खनिज, वन्य प्राणियों का शिकार आदि में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का तांडव होता रहता है इस दम पर वहां बैठे और रेंजर एसडीओ डीएफओ सीसीएफ वसूली

कर महीना पहुंचते हैं। वन मंत्रालय में प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक बने प्राणी कार्य योजना उत्पादन अनुसंधान एवं विस्तार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा, मानव संसाधन विकास, प्रशासन राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, समन्वय, संरक्षण, विकास, वित्त बजट, संयुक्त वन प्रबंधन, नीति विश्लेषण इकाई, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक वन प्रबंधन, परियोजना, प्रोजेक्ट्स, सतर्कता एवं शिकायत, विश्व खाद्य कार्यक्रम, भू प्रबंधन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, इको पर्यटन बोर्ड, राज्य वन विकास निगम, लघु वन उपज संघ, मध्य प्रदेश राज्य बंबू मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, निगरानी एवं मूल्यांकन, विशेष कार्य बल पुलिस विभाग मध्य प्रदेश भोपाल वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो आदि विभिन्न शाखाओं में हजारों करोड़ों खर्च करने के बाद में भी ना तो वनों का विकास हो पा रहा है। ना ही वन्य प्राणियों का संरक्षण और विकास हो पा रहा है। सारा पैसा वनेले सूकरों द्वारा हजम किया जा रहा है।

उपरोक्त पत्र घोर भ्रष्ट जालसाज मुख्य वन संरक्षक सनोड़िया जिसके पास मुख्य वन संरक्षक इंदौर व्रत के प्रभार के साथ सामाजिक वानिकी इंदौर वृत्त का भी प्रभार है। स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रभार के लिए उस हरामखोर जालसाज वन माफिया का संरक्षक दाता सनोड़िया को कैसे प्रभार मिला होगा। इस मोटी चमड़ी के सुअर ने मोटा पैसा खर्च किया होगा। तब ही इस भ्रष्ट को दो महापुर पदों का प्रभार मिला। यही कारण है कि यह सूअर सूचना के अधिकार में पत्र देने पर वापस कर देता है जैसे पूरा वन विभाग इसके बाप की जागीर हो। इंदौर में वन भूमि पर कब्जे कालोनियां काटना भू माफियाओं को सरंक्षण देना उस पर पट्टे बांटना का बहुत बड़ा जिसमें हजारों करोड़ की वन भूमि पर कब्जे करवा दिए गए चाहे वह रालामंडल के बाईपास होसुपर कॉरिडोर हो वह अन्य स्थानों पर वन भूमि पर अतिक्रमण, खनन, वृक्ष कटाई इंदौर, चोरल, मानपुर, पेड़मी रेंज में,महू सब स्थानों पर चल रही है और उसमें मोटा पैसा हजम किया जा रहा है। इसलिए यह सूअर के पिल्ले सूचना का अधिकार मंच जानकारी देने की अपेक्षा आवेदन ही वापस कर देते हैं और नई नई दलीलें देते हैं दूसरी तरफ सूचना आयुक्त का कोई निर्णय कानून नहीं बन जाता।

वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से लेकर पीसीसीएफ तक सबके मोबाइल की पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग सरकार देख ले तो मालूम पड़ जाएगा कौन कितना भ्रष्टजल साइज चालबाजहोने के साथकिस प्रकार से अपनी मोटी कमाई के लिए वन भूमि वनोंपज, वनों वृक्षों, वन्यप्राणियों वन खनिज के साथ वहां काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी मजदूरों आदि के भुगतान में भ्रष्टाचार किया जाता है सारा सच सामने आ जाएगा।

वन मंत्री विजय शाह की दादागिरी, अय्याशी, वनों की कटाई, वनभूमि पर अतिक्रमण, खनन का लंबा पुराना इतिहास रहा है। फिर वोटों की राजनीति के चलते पट्टे बांटने का षड्यंत्र पिछले 20 साल से अनवरत चल रहा है। जिसमें जानबूझकर, ग्रामीण जो भरी गर्मियों में, पूरे प्रदेश के जंगलों में तेंदूपत्ता को तोड़ने जाते हैं वह तेंदूपत्ता बटोरने के साथ-साथ वहां पर साफ सफाई करके मक्का फैला देते हैं जो बरसात आते ही बढ़ने लगती है और उस मक्का की बड़ी फसल की आड़ में, वृक्षों की कटाई का क्रम शुरू हो जाता है। बाद में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर कि हम वहां पर फसल बो रहे हैं। वन कर्मी हमें परेशान करते हैं हमारी फसलें बर्बाद करते हैं और औरतों को छेड़ते हैं। शिकायत होते ही कार्रवाई होती है और 1 कर्मी छेड़छाड़ के गंभीर संगीन आरोपों से बचने वहां जाना बंद कर देते हैं बाद में भर जमीन यह दिखाई जाती है कि वहां बरसों से फसल बो रहे हैं। हमें पट्टा दिया जाए।

शक इस बीच कुछ बंद करनी उनसे सांठगांठ कर लेते हैं और महीना लेकर उन्हें फसल बोने की खुली छूट दे देते हैं। यह वन भूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र पूरे मध्यप्रदेश मैं पिछले 20 वर्षों से खूब फल फूल रहा है। इस प्रकार नियमित फसल बोना शुरू कर दी जाती है। और फिर वे ग्रामीण वन कर्मियों को वन क्षेत्रों में घुसने देने की अपेक्षा मारपीट करके भगाना शुरू कर देते हैं। यह सारे कांड महू उसके आसपास भी बहुत हुए हैं। अब इस प्रकार इस षड्यंत्र में वन्य प्राणियों के विचरण का क्षेत्र तो हथिया लिया गया। स्वाभाविक है वेयर बस्तियों में घुस आसानी से शिकार करने लगे।

दूसरी तरफ पूरे वन विभाग में स्टाफ की तो 70% कमी है। ही। इसके साथ ही सारे वन विभाग कि हर शाखा में पिछले 20 सालों से पदोन्नति व भर्तियां तो नहीं हुई। तो स्टाफ कम होना स्वाभाविक था। वर्तमान हालत में 1-1 बीट गार्ड के पास लगभग 4 से 5 बीट का 24 घंटे का प्रभार होता है। जबकि हर 8 घंटे में हर बीट में एक बीटगार्ड की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। ताकि सही तरीके से जंगलों की भूमि संपत्तियां, वनोपज, खनन निगरानी कर नियंत्रित किया जा सके।

फिर भेड़िया झुंड पार्टी की सत्ता में तो जो जितना बड़ा भ्रष्ट उससे मोटी रकम व महीना बांध उसको ऊतना कमाई वाला पद दिया जाता है। इंदौर में बैठा वन मंडल अधिकारी पांडवा भी वन मंत्री मुख्यमंत्री प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सारी सेवाएं देकर ही तो इंदौर में 3 साल से ज्यादा समय से पदस्थ है। जिसने इंदौर में पदस्थ होते ही सबसे पहले डीएफओ सीसीएफ के व अन्य विभागीय कर्मचारियों के निवास गृहों मैं लाखों रुपए के काम कागजों पर करवा कर हजम कर लिए थे। यही कारण है कि यह हरामखोर जब भी सूचना के अधिकार में आवेदन लगाओ। तो बिना देखे समझे यह 1 प्राणी उत्तर लिख देता है की केवल एक बिंदु की जानकारी मांगे। और आवेदन खत्म। अपील लगाने पर वहां आया घोर बदतमीज वनरक्षक सनोड़िआ जिसके पास नियमित वन सीसीएफ के साथ सामाजिक वानिकी व अनुसंधान का वन नर्सरियों का प्रभार भी है यह भी घोर भ्रष्ट व व जालसाज होने के साथ भारी अकड़ में रहने और सूचना के अधिकार के आवेदनों को भी लौटा देता है।

फिर रालामंडल, के साथ महू, सिमरोल व अन्य उप संभागों में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचारों की खबरें आप समाचार पत्रों में सतत पढ़ ही रहे हैं। तो स्टाफ के अभाव में महू उप संभाग के मलेंडी बीट में जो बाघ द्वारा सुंदरलाल के शिकार की घटना घटी। उसके डीएफओ पंडवा के साथ वन्य प्राणी टाइगर फोर्स भी जिम्मेदार है। जिसमें बहुत कम स्टाफ है। जिसके पास अगर सूचना होने के बाद में भी उसने समय रहते आवश्यक सावधानियां नहीं बरतीं।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सभी आयातित इंजीनियर लूटो भ्रष्टाचार करो और चलो

ठेकेदारों के साथ मिलकर गुणवत्ता का कारण ही वसूली की व्यवस्था

(समय माया)

मध्य प्रदेश ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण में उसके प्रारंभ से लेकर अभी तक यहां पर सभी इंजीनियर ग्रामीण यांत्रिकी से लेकर लोक निर्माण विभाग जल संसाधन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी गृह निर्माण औद्योगिक केंद्र विकास निगम, से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कंपनियों के इंजीनियरों पदस्थ की जाती है जिनका दूर-दूर तक सड़क से कोई वास्ता नहीं होता बैठा दिए जाते हैं।

स्वाभाविक है कि उन्हें सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा के समय का ही जो ज्ञान होता है उसी के दम पर वे एस ग्राम सड़क परियोजना कार्य में कार्य करने के लिए आ जाते हैं स्वाभाविक है उनके लिए सड़कों का स्तर कार्य की पद्धति कार्य की गुणवत्ता से कहीं ज्यादा क्योंकि वह धन खर्च करके ही इस विभाग में आते हैं स्वाभाविक सी बात है कार्य गुणवत्ता की अपेक्षा मोटी कमाई का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण में सारी भूमि ग्रामीणों से पंचायतों की सरकारी चरनोई की नजूल की मुफ्त की भूमि का ही सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। निसंदेह गांव की सड़कों से जोड़ने पर ग्रामीणों को खुशी तो होती है पर यह खुशी तब दुख में बदल जाती है जब किसान का सड़कों के निर्माण के कारण बरसात के दिनों में सड़क के गलत तरीके से और पानी की पर्याप्त निकासी ना होने के कारण सड़कों के बन जाने के कारण उनके खेतों में भर जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है स्वाभाविक सी बात है जिन इंजीनियरों को इस बात का एहसास ही नहीं होता क्योंकि सड़क निर्माण के बाद पानी की पर्याप्त निकासी ना देने के कारण जिन किसानों ने अपनी भूमि सड़क निर्माण के लिए दान में दी थी वह उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। जिसके पीछे यही आयातित इंजीनियरों का अधूरा और उथला ज्ञान ही जिम्मेदार होता है और हर जिले में बनी हुई परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा बनाई हुई सड़कों में हर सड़क से जुड़ा हुआ ऐसा खेत जिसमें निर्माण के समय पानी की सड़क की ऊंचाई बढ़ जाने के कारण पर्याप्त निकासी ना होने से दस बीस परसेंट सड़क किनारे के गांवों को यह नुकसान लगातार झेलना पड़ रहा है जिसके लिए यहां के डीपीआर बनाने वाले

उपयंत्री सहायक यंत्री महाप्रबंधक से लेकर मुख्य महाप्रबंधक तक सब जिम्मेदार होते हैं परंतु भ्रष्टाचार के चलते किसानों की ऐसी आवाज को कोई नहीं सुनता जबकि होना यह चाहिए की पहली ही बरसात में सड़क बन जाने के बाद ऐसे जितने भी किसान इस संकट के शिकार हुए हैं उन्हें अगली बरसात आने से पहले उनके खेतों में पर्याप्त जल निकासी के लिए छोटी पुलिया की व्यवस्था की जानी चाहिए दूसरी तरफ सच यह भी है की सड़क निर्माण के बाद दोनों तरफ खुदी जाने वाली नालियों का निर्माण ही ढंग से नहीं होता जबकि हर सड़क निर्माण के प्रक्रम में नालियों के निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था का व्यवहारिक प्रावधान किया जाता है परंतु भ्रष्टाचार के साथ चलते और आयातित इंजीनियरों की वसूली की मानसिकता के चलते दोनों तरफ पर्याप्त नालियों की खुदाई नहीं होती है साथ ही साडे 6 मीटर की सड़क में दोनों तरफ डेढ़ लीटर की पट्टियां भरने में भी जो कच्ची मोरम से सड़क तक समतल पट्टियां भरी जानी चाहिए उनमें भी ढंग से भराई नहीं की जाती। और पैसा हजम कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हर छोटे से छोटे गांवों में वाहनों की संख्या में न केवल मोटरसाइकिल बल्कि चार पहिया वाहनों, ट्रैक्टरों ,कारों, मिनी ट्रकों की भी पिछले 10 सालों में काफी वृद्धि हो चुकी है स्वभाविक है की सड़कों पर यातायात का भार बढ़ने से यह सड़कें कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए जिसमें 6 मीटर डामरी कृत वाहन चलने योग्य सड़क व डेढ़ मीटर की दोनों तरफ सोल्डर पटिया होनी चाहिए। क्योंकि वाहनों के बढ़ने से गांव के युवा बच्चे सड़कों की चौड़ाई कम होने से सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त इन्हीं सड़कों पर सामने से आने वाले वाहन के कारण हो रहे हैं। जो कुल 9 मीटर की चौड़ाई भविष्य के लिए आवश्यक है। परंतु वर्तमान में 3.75 मीटर की सड़क और 1.125 मीटर की दोनों तरफ की सोल्डर पट्टियों का निर्माण किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप इस चित्र में देख रहे हैं मिट्टी कार्य को भी पानी डालकर रोलर कैसे दबाया बनाया जाना चाहिए दानेदार उप आधार को भी पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ मोरम होना चाहिए जो की गिट्टी या नदी की रेत से पत्थर का चूरा भरा जाना चाहिए वह सब कुछ नहीं होता वहीं की काली मिट्टी को पलटा कर उसमें ही पत्थरो व गिट्टी की भराई करके कार्य संपन्न करके मोटा पैसा हजम कर लिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है इस मोटी कमाई का हिस्सा उपयंत्री सहायक यंत्री के साथ महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक प्रमुख अभियंता सीईओ सड़क विकास प्राधिकरण मंत्री ग्रामीण विकास प्रधान सचिव ग्रामीण विकास मैं बढ़ने के साथ-साथ गांव के सरपंच वहां के विधायक और सांसद को भी हिस्सा बांटना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है पैसा भले ही केंद्र सरकार दे बेशक केंद्र सरकार के मापदंड बहुत ठोस और स्तरीय होते हैं पर कार्य करवाने वाले घोर भ्रष्ट होते हैं इसलिए यह कार्यक्षमता गारंटी की सड़कें दी समय पूर्व खराब हो जाती हैं।

यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी ना देने के लिए कम से कम इंदौर उज्जैनसंभाग की 20 से ज्यादा इकाइयों में घोर भ्रष्ट इंजीनियर होने के कारण वह बहाने ज्यादा बनाते हैं और उनके संरक्षक मुख्य महाप्रबंधक इंदौर कासि?ह व उज्जैन का दशोरे पहले तो अकेले ही पी जाते हैं पर ज्यादा दबाव डालने पर सारी सुनवाई करने के बाद मैं भी अपने महीना बांटने वाले महा प्रबंधकों को बचाने के लिए उल्टे सीधे आदेश देकर जानकारी देने से आवेदकों को वंचित करने का प्रयास करते हैं। वैसे इसके पूर्व में भी बिलों की वसूली में कई इंजीनियर प्रदेश भर में और लोकायुक्त के लपेटे में आ चुके हैं।

मप्र लो स्वा यां. मं. मोटी कमाई के लिए चौहान के पास

पेयजल आपूर्ति और निकासी की आड़ में हजारों करोड़ों का खेल

रुपए 45000 करोड़ के खेल में 30% हजम

(समय माया)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल में सभी विभागों में लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार कर चुका हैजो भी अधिक बजट वाला विभाग होता है वह चौहान मोटी कमाई और लूट के लिए चीज अपने हाथ में रखता है जैसे नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यंत्र की अधिकांश पैसा केंद्र का जो लगभग 45000 करोड़ से ऊपर था मध्य प्रदेश में आया। और वह पैसा विश्व बैंक ने ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कर्ज के रूप में दिया जिसे भारत सरकार ने दिसंबर 2019 मेंजल शक्ति मंत्रालय के गठन को उपरांत पेय जल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन दिसंबर 2019 में प्रारंभ किया गया है। मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाना लक्षित किया गया है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल से जल हेतु घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम सेपेयजल करवाने के लिए 50-50% केंद्र व राज्य का वित्त उपलब्ध करवाया है। इस योजना के अंतर्गत हैंड पंप योजनाओं से जलप्रपात 55 लीटर प्रति व्यक्ति वह नल जल योजना के माध्यम से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति निर्धारित की गई है। प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रपात योजनाएं भूगर्भीय जल स्रोतों मुख्यतः नलकूपों पर आधारित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को उसके निवास से अधिकतम 300 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध करवाना है पहाड़ी क्षेत्रों में 30 मीटर की ऊंचाई या नीचे पर पेयजल उपलब्ध करवाना है।

स्वाभाविक है पूरे विभाग में ग्रामीण जल आपूर्ति के नाम पर वहां बैठे उप व सहायक, कार्यपालन अधीक्षण यंत्री व मुख्य अभियंता इसकी भारी बंदरबांट में लगे हुए हैं। नीचे से ऊपर तक पूरे प्रदेश मैं 55 ग्रामीण संभागों, 8 विद्युत एवं यांत्रिकी संभागों में घोर भ्रष्ट जालसाज मुख्य व प्रमुख अभियंता को मोटे कमीशन पर बैठा रखा है। जालसाज भेडिया झुंड पार्टी ने अपनी मोटी कमाई करने के लिए भर्तियां व पदोन्नतियां न किए जाने के कारण, पूरे विभाग का स्टाफ 33% रह गया स्वाभाविक है। आबादी और

योजनाएं बढ़ने के कारण काम चार गुना हो गया।

देसी था कम से कम स्टाफ होगा ज्यादा से ज्यादा लूट की जा सकेगी और चौकी इस विभाग में जनदायित्व के अंतर्गत हर मौसम में प्रदेश की पूरी आबादी को खास तौर पर ग्रामीण आबादी को जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी है। जिसकी आड़ में न केवल प्रमुख अभियंता अंधवान, बल्कि घोर भ्रष्ट व जालसाज प्रमुख अभियंता इंदौर सोलंकी जिसके अंतर्गत 15 जिले हैं, भोपाल आर हीरोदिया ग्वालियर आर एल एस मोर्य, जबलपुर एच एस गौंड, भ्रष्टाचार और लूट का रिकॉर्ड रहा है इसीलिए सब मोटा धन देकर प्रभारी मुख्य अभियंता बना दिए गए हैं। बीपी सोनकर जिसके पास 11 विद्युत यांत्रिकीय संभाग और 50 उप संभागों में बैठे सहायक यंत्री मशीनों की रिपेयरिंग पाइप मोटर हैंड पंप आदि माल की खरीदी कई गुना ज्यादा मोटे कमीशन पर कर लेते हैं इसका सीधा पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता है।

प्रदेश के 55 से ज्यादा संभागों में चले जाइए वहां करोड़ों रुपए का माल सड़ता रहता है उपयोग नहीं होता परंतु खरीदी हर वर्ष केवल कमीशन के लिए की जाती है जब इन हरामखोर से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगो तो इंदौर में बैठा मुख्य अभियंता विजय सिंह सोलंकी ना अपने कार्यालय की जानकारी देता है ना ही आवेदक को अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजता है क्योंकि इन सबको अपने संभागीय यंत्री से महीना मिलता रहता है इसलिए सबको बढ़ाने का षड्यंत्र करते हैं। दूसरी तरफ इन भ्रष्ट डकैतों ने 18 साल गुजर जाने के बाद मैं भी 17 व 8 कल 25 बिंदुओं की जानकारी अभी तक अपनी साइट पर लोड नहीं की सब जन-धन को अपने आप की जागीर समझते हैं इसलिए कोई भी खरीदी सामग्री का उपयोग आदि की जानकारी कभी नहीं देते और स्टॉक इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। जानकारी नहीं देते और लिख देते हैं कि हमारे यहां स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता क्योंअपने आप की जागीर है जो मनचाही खरीदी करो मनचाहा स्टॉक बेंचो व बड़ा दो। यह शुक्राणु की फौज अगर स्टॉक की जानकारी देगी तो उप यंत्री से लेकर प्रमुख अभियंता तक सारे वीडियो का झूठा भ्रष्टाचार के लपेटे में आकर फंस जाएगा। फिर अगर जानकारी देने की नियत नहीं हैतो जलसा जो 18 साल गुजर जाने के बादभी अभी तकसारी जानकारी 25 बिंदुओं की अपनी साइट पर लोड क्यों नहीं करते जनता को पेट्रोल डीजल गैस में डूबते रहो और लूट का पैसा अपने आप की जागीर समझकर हजम करते रहो कोई कुछ ना बोले जानकारी मांगने पर बदतमीजी पूर्ण तरीके से उसके जवाब दिए जाएं जवाब और आवेदक को हाथों सहित करने का हर कदम कदम पर प्रयास किया जाता रहे। दूसरी तरफ जल निगम बनाने का उद्देश्य यही था की शासकीय कार्य पद्धतियों में लपेटे में ना आए और जल निगम है तो उसके ना तो ऑडिट हो और ना ही उसमें केंद्र सरकार का संभागीय लेखाकार बैठकर हर कार्रवाई पर नियंत्रण कर सके क्योंकि जल निगम बन गया है वह एक लाभ कमाने वाली संस्था है तोजो विश्व बैंक का पैसा मिलता है उसके अंतर्गत सारे गांव में बड़ी-बड़ी योजनाओं में बड़ी-बड़ी डीपीआर बनाकर आसानी से पैसा हजम करो सुविधा दे सको ना दे सको परंतु शासकीय कार्रवाइयों और कानूनी कार्रवाइयों से बचे रहो।

गांव में जो योजनाएं बनाई गई है वह आधी अधूरी बन बनकर सरपंचों को सौंप दी गई है सरपंच उन योजनाओं को और उसके पानी को भी अपने आप की जागीर समझता है वह ग्रामीणों को जलापूर्ति करने की अपेक्षा अपने खेतों के साथ अपनी कारों गए दोनों जानवरों को नहलाने में नलकूपों का अपने स्तर पर उपयोग करता रहता है और ग्रामीण प्याज से मारते रहते हैं जैसा कि देवास के संसद के गोद लिए गांव अजनास में देखने को मिलता है। जनता को जल मिले ना मिले परंतु जैन-जल के नाम पर सरपंच उप यंत्री से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री अपने बैंक खातों को अवश्य सींचते रहते हैं।

साप्ताहिक समय माया

विश्व घातक संगठन की कठपुतली हैं खाद्य व औषधि विभाग

खाद्य सुरक्षा अधिकारी व औषधि निरीक्षक डकैतों की फौज

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए 20 करोड़ से ज्यादा खाद्य व्यवसायियों को कानूनों में उलझा नष्टकरने का षड़यंत्र

(समय माया)

पूरे देश व राज्यों का स्वास्थ्य विभाग व इस की अन्य शाखाएं जिसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रशासन व औषधि नियंत्रण विभाग का पूर्ण नियंत्रण दुनिया को अपने आप की जागीर समझने वाले संकर वर्णीय प्रजाति के गौर जालसाज डकैत अमेरिकी षड़यंत्रकारी संगठन वर्ल्ड हेजार्डस ऑर्गेनाइजेशन या विश्व घातक संगठन जो कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेजॉन वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट केसाथ अमेरिकी दवा उपकरण टीका उत्पादक कंपनियों विजाग मॉडर्न डॉक्टर एंड गैंबल, जॉनसन एंड जॉनसनआदि सैकड़ो के धन पर पलने वाला व उनके इशारे पर नाच कर दुनिया को भ्रमित करअपना माल बेच मोटी कमाई करना और गुलाम बनाने वाला संगठन के इशारे पर नाच कर देश के 25 करोड़ पारंपरिक उद्योगों, खाद्य सामग्री निर्माता विक्रेताओं को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा है। देश में अमेरिकी कंपनी वालमार्ट जिनके सहयोग से भारत में बिग बाजार व भारत की रिलायंस फ्रेश जो रिलायंस रिटेल, टाटा बिग बास्केट अदानी बिरला मित्तल डी मार्ट आदि के इशारे पर थोपा गया खाद्य सुरक्षा मानक अधि 2006 जिसके अंतर्गत सभी खाद्य वस्तुओं को पैकेजिंग करके बैठने के नाम पर कई गुना कीमत वसूल करने के साथ पैकेजिंग में प्रिजर्वेटिव्स और कीटनाशक मिलने के कारण वह आर्थिक घातक हो जाता है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का खाद्य नियंत्रक मानता है 96.4% पैकेज खाद्य भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक है।

इसके विपरीत यह जालसाज हरामखोरों का झूठाविश्व घटक संगठन के सारे पढ़ना आजका जनता को लूटने और मोती वसूली करनेसारे शॉपिंग मॉलकिसानों से खाद्य वस्तुएं खरीद कर उसको पैकेजिंग के नाम परकई दिनों की कीमत ठोक देते हैं। दूसरी तरफ इनके शॉपिंग मॉल की बिक्री बढ़ाने के लिए 25 करोड़ से ज्यादा छोटे खाद्य विक्रेता निर्माता पैकर्स और उद्योगों को खत्म करने के लिए विश्व घटक संगठन के सारे पर चलाई जा रहे ईट राइट प्रोग्राम जिस दुनिया को भारत के आयुर्वेद में खाना पीना रहना और जीवन जीना सिखाया हो उसे देश मेंविश्व घातक संगठन के सारे परआईटी राइट कार्यक्रम जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा छोटे व्यापारियों दुकानदारों खाद्य विक्रेताओं चाय पान की होटल कचोरी समोसे नमकीन पानी पतासे फल फूल बेचने वालों को ये हरामखोर जालसाजों का अड्डा को खत्म करने में उलझाने ईट राइट प्रोग्राम खाद्य पदार्थ बनाना पैक करना भोजन बनाना बेचना खाना सिखाएगा। देश की भेड़िया झुंड पार्टी की केंद्र की व राज्यों की सरकारें विश्व घातक संगठन से पैसा खाकर किस प्रकार से बहूराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच कर अपने ही देश के मुझको तो जीवन यापन करने वाले थे लोग गुमटियों में चाय पान से लेकर छोटा-मोटा साधारण पारंपरिक नाश्ता बैचने वालों को ये हरामखोर वसूली बाज खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो अधिकांश करोड़पति हैं। लाखों की कारों मैं 15 से रु. 30000 का पेट्रोल फूंक चलाकर खाद्य व्यवसाय उद्योगी दुकानों परअपना जलवा पेलकर हजारों रुपए प्रति दुकान ठेलों से, दूध बेचने वाले मोटरसाइकिल वालों से लेकर ट्रकों से लाखों रुपए प्रति माह की वसूली करते हैं। जिनके गृह नगरों और निवास स्थान पर लाखों के दूसरों के नाम से फ्लेट प्लॉट और मकान खरीदे हैं। इन सब हरामखोर जालसाजोंके मोबाइल फोन

की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की जाति और देखा जाता कि यह किस प्रकार का कहां से कितना भ्रष्टाचार कर वसूली कर रहे हैं।

यही हाल औषधि निरीक्षकों का है यह औषधि निरीक्षक भी सभी दवा विक्रेता दुकानदारों उत्पादकों से महीना वसूली करते हैं। इसीलिए यह पूरा विभाग सूचना के अधिकार में ना तो 18 साल में सारी जानकारी अपनी सीटों पर लोड कर पाया और ना ही किसी आवेदक को उपलब्ध करवाता है और जमीन की अपील लगाई जाती है तो वहां बैठा हुआ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, खंडवा, खरगोन और पूरे मध्य प्रदेश क्योंकि इन सब खाद्य एवं औषधि निरीक्षक से महीना वसूली करता है इसलिए अधिकांश अपीलें रद्द कर दी जाती है? इस प्रकार यह विभागभी विश्व घातक संगठन के इशारे पर नाच कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए पूरे के पूरे देश के 20 करोड़ से ज्यादा खाद्य व्यवसायियों को इन जालसाजी पूर्ण कानूनों में उलझा कर नष्ट करने पर तुला हुआ है।

'जालसाज राक्षस पुंजी पतियों बहुराष्ट्रीय कं. द्वारा सत्ता मैं बैठे नेताओं अधिकारियों को खरीद कर कानून बनवा कर के करोड़ों छोटे दुकानदारों ठेले वालों फुटपाथ पर माल बेंचने वालों को बेरोजगार कर अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर जनता की जेब पर हजारों गुना महंगा माल जिसमें घातक कीटनाशक, रसायन मिला पैकेज्ड माल बेंच डकैती डाल घातक बीमारियों का शिकार बनाने वाले, शॉपिंग माल्स में पूरी दुनिया में भूख से मरते गरीबों बेरोजगारों द्वारा ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हर दिन घटती हैं।

ऐसी घटनाएं जनता में बढ़ती बेरोजगारी, से निर्धनता भुखमरी के कारण दिनों दिन बढ़ेंगी ही घटेगीं नहीं। मरता क्या नहीं करता।

अफ्रीकी देशों में तो कोई भी शॉपिंग माल शाम को 6:00 बजे के बाद खुला नहीं रह सकता क्योंकि इन षडयंत्रों के कारण वहां के निर्धनता और भूख से मरते लोग ऐसे ही डकैतों के शॉपिंग मॉल्स लूट कर अपनी भूख मिटा पाते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है, कि इन शॉपिंग मॉल्स को खत्म कर करोड़ों लोगों को रोजगार दे किसानों की फसलों को तत्काल ताजा साफ सुथरा बिना मिलावट का खाद्य पदार्थ सस्ती कीमतों पर जनता को उपलब्ध करवा ने सरकारों को पैकेज्ड फूड से संबंधी सारे कानून जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को खत्म किया जाना चाहिए। ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट डकैती खाद्य पदार्थों पर शॉपिंग मॉल का एकाधिकार खत्म किया जाना चाहिए। किसने बनाया हमारे युवाओं को नपुंसक।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वॉलमार्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट व सैकड़ों अमेरिकी दवा उत्पादक कंपनियों के इशारे पर नाच और उनका धन खाने वाले विश्व घातक संगठन जिसने भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 बनवाकर सभी खाद्य वस्तुओं में प्रिजर्वेटिव्स कीटनाशक मिलाकर पैक करने व देसी खाद्य को सड़ा गला स्तर हीन बीमारी वाला बता कर विज्ञापन पेल पेल कर उसको खाने के लिए मजबूर करने के कारण उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खाने से हमारे युवाओं को बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल नपुंसकता जैसी बीमारियां हो जाने के कारण और उसके ऊपर घातक एलोपैथिक दवाओं के खाने से हमारे युवा कमजोर और नपुंसकों हुए जा रहे हैं। उसके लिए यह कसाई एलोपैथिक डॉक्टर और पैकेज फूडपूर्णता जिम्मेदार है।

तो नीच कसाई डॉक्टर पहले युवाओं को नपुंसक बना बांझ बना और उसमें भी कमाई करो और फिर उनको परख नली शिशु से पैदा करो। अपने अम्मा और बाप से पूछ लो डॉक्टरों कि तुम्हारा असली बाप कौन है किसके बीज से तुम्हारी अम्मा ने तुमको पैदा किया?

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 22-23 से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 22-23 बकवास, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, चाइना को लाभ

घोर लालची मोदी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और चाइना का रखेला है। यह कानून चीन माइक्रोसॉफ्ट गूगल को फायदे के लिए

(समय माया)

भारत सरकार की औकात भी नहीं कि ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल के भारत के डाटा जो उनके पास सारे आधार कार्ड पैन कार्ड की व जुड़े बैंकों के 300 करोड़ खातों की जानकारी को जो उनके पास पहले ही पहुंच चुकी है। के षड्यंत्रों को, चीनी कंपनियों के उपयोग किए जा रहे 80% मोबाइल अर्थात 140 करोड़ मोबाइलों के माध्यम से प्रतिदिन की जानकारी जो चीन में सीधे ही इकट्ठी हो चुकी व रही है। उसको मांग सकें व रोक लें।

दूसरी तरफ भारत के आईटी विशेषज्ञ जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लाखों करोड़ की कमाई करते हैं हर साल, पर भारत में गूगल माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट सर्च इंजन आदि के विकल्प ढूंढ कर सारे डेटा को रोक सकें। आश्चर्य इस बात का है, कि आज सभी शासकीय विभागों का कार्य गूगल शीट गूगल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल के जीमेल आदि का उपयोग कर उस के माध्यम से किया जा रहा है। यहां तक की सभी विभागाध्यक्ष इसमें शिक्षा स्वास्थ लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, गृह निर्माण मंडल महिला बाल विकास, वन, जीएसटी, शहरी विकास, विद्युत कंपनियों, आयकर, डाक, रक्षा मंत्रालय आदि 200 से ज्यादा विभागों के संचालक प्रमुख अभियंता आयुक्त स्वयं ही गूगल शीट का प्रयोग करने के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बोलते हैं। तो सारा डाटा तो स्वयं सरकार ही अमेरिका को पहुंचा रही है।

तो भारत के डिजिटल परसनल डाटा बिल क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए बनाया जा रहा है।

जब स्वयं ही मोदी जो सन 2014 के पहले तक आधार कार्ड और उसके डाटा का विदेशों में जाने के कारण विरोध करता था। 2014 के बाद ना केवल आधार कार्ड को बैंकों से ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड से लेकर ना केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के डाटा को भी जोड़ने भेजने के लिए मजबूर किया गया जबकि 2006 से ही मैं हीं लगातार उसका विरोध करता रहा। वही नंदननील केणी जिसने यह आधार कार्ड की योजना लागू की थी।

उस डाटा की बिक्री से हजारों करोड़ रुपए कमा चुका था। उसी धन से वह 375 करोड़ रुपए दान कर चुका है। इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। परंतु जब सत्ता ही जाहिलों मूर्ख भूखे भेड़ियों के हाथ में हो। चारों तरफ भुखेरे डरपोंक अंडभक्तों की हुआ हुआ करने वाली फौज खड़ी हो। तो भैंस के सामने बीन बजाने से भी वह दूध भी तो ज्यादा नहीं देती। भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद के ऊपरी और निचले दोनों सदनों से पारित हो गया है और जल्द ही कानून में हस्ताक्षरित हो जाएगा। कानून किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को सही करने या मिटाने का अधिकार स्थापित करता है और डेटा संग्रह, प्रसंस्करण, साझाकरण और हस्तांतरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता है। यह विधेयक भारत में गोपनीयता कानून पारित करने के कई प्रयासों का नवीनतम पुनरावृत्ति है, जिसमें 2019 का प्रस्ताव भी शामिल है जिसे इसकी सख्त डेटा ट्रांसफर आवश्यकताओं पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। हालाँकि, मौजूदा कानून को सरकार को दिए गए कई अपवादों और शक्तियों के कारण गोपनीयता समर्थकों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में कई लोगों का कहना है कि इससे सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी। कानून के तहत, सरकार राज्य एजेंसियों और अन्य निकायों को कानून का पालन करने से छूट दे सकती है, सरकार को डेटा सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने की अनुमति देती है जो शिकायतें सुनेगी, और सरकार और डेटा सुरक्षा बोर्ड को कानूनी कार्रवाइयों से बचा सकती है। यह देखना बाकी है कि क्या यह कानून वास्तव में गोपनीयता की रक्षा करता है या सरकारी गोपनीयता के दुरुपयोग के लिए दरवाजा खुला रखता है।

राजस्व, वाणिज्य कर, पंजीयन आबकारी विभाग की प्रधान सचिव 6 साल से दीपाली रस्तोगी

मप्र वाणिज्य कर आयुक्त की अकर्मण्यता व होशियारी

(समय माया)

वाणिज्य कर में बैठे हरामखोरों जो बरसों से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठे हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया जाता क्योंकि मोटा धन हर महीने आयुक्त प्रधान सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जिनका सारा माल अब जनता को कई गुना कीमत पर शहर के शॉपिंग मॉल से लेकर गली मोहल्ले व प्रदेश के 30,000 गांवों की छोटी किराना दुकानों तक अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, आईटीसी, युनिलीवर, आदि का स्वास्थ्य घातक पेकेज्ड, खाद्य पदार्थ व अन्य सामग्री बिक रही है इन सबसे मोटा महीना मुख्यमंत्री मंत्री प्रधान सचिव आयुक्त तक को मिलने के कारण, जीएसटी की धारा 68 और 71 में मालवाहकों पकड़ने के लिए खोले गए एंटी इवेजन विंग को पिछले डेढ़ साल से पावर नहीं दिये जा रहे। जबकि प्रदेश सरकार चाहे तो 40 नाकों को पुनः चालू कर वर्तमान कर वसूली को डेढ गुना किया जा सकता है।

इस प्रकार वहां पर भी लगभग 50 से 70% तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट देकर हानि करवाई जा रही है। अदानी जबकि जीएसटी 18-28% है जबकि उसे पूरी छूट दे दी गई। यही हाल उसके मित्रों अंबानी टाटा बिरला मित्तल आईटीसी युनिलीवर व अन्य सभी बड़ी कंपनियों का है। जो शीर्ष पर बैठे मंत्री प्रधान सचिव वह नीचे बैठे अधिकारियों को मासिक वेतन बांटकर सारा षड्यंत्र कर देश प्रदेश के राजस्व को हानि पहुंचाते हैं। बदले में आम जनता छोटे व्यापारी उद्योगपति को ही पिसना पड़ता है। राजस्व, वाणिज्य कर, पंजीयन आबकारी विभाग की प्रधान सचिव 6 साल से दीपाली रस्तोगी घोर भ्रष्ट ही है। प्रदेश के राजस्व की आय के मुख्य स्त्रोत हैं। पंजीयन में संयुक्त व जिला पंजीयक के रूप में अकेले 6 साल से इंदौर में घोर भ्रष्ट बीके मोरे बैठा हुआ था। उप पंजीयकों में अनेकों को पूरे प्रदेश में मोटी लूट व वसूली के चलते एक ही पद पर 5 वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थ कर रखा है। जबकि भू माफिया कॉलोनी माफियाओं द्वारा हर क्रय विक्रय में शासन को 20 से 80% तक की हानि हो रही है। जैसा कि अंकेक्षण सूचना व जांच व शिकायतें बता रही हैं। पंजीयन में बैठे जिला पंजीयक से लेकर उपपंजीयक तक भ्रष्टाचार के धन से घमंड में डूबे हरामखोर जालसाज इतने बदतमीज होते हैं की सूचना के अधिकार को जानकारी मांगने पर साफ मना के लिखने के बाद उनकी अपील कलेक्टर को दो तो वह हरामखोर जो इन सब से महीना वसूलता है। जैसा कि देवास उज्जैन और धार में हुआ। मैं साफ मना कर दिया की जानकारी देना बाध्यता नहीं। जैसे इन जालसाजों के बाप की जागीर हो। यह कुछ भी भ्रष्टाचार करें और सूचना के अधिकार में जानकारी ना दें क्योंकि उनके सारे आका जिला पंजीयक, कलेक्टर, आयुक्त से लेकर महा निरीक्षक मुद्रांक व प्रधान सचिव सब उनके पाले हुए श्वानों को वह टुकड़ा डालते हैं महीने का। इसलिए भ्रष्टाचार के धन से उनका धनांध व बदतमीज होना स्वाभाविक है।

वही हाल आबकारी विभाग के जिलाधिकारियों, उपायुक्तों, आयुक्त से लेकर दीपाली रस्तोगी व व मंत्री जगदीश देवड़ा तक का है। बेशक यहां पदस्थी, स्थानांतरण, स्थायित्व, आदि के लिए मोटा धन लगता है। बेशक यहां पर भी हर मैदानी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार से धनांध होता है। शराब देसी विदेशी में अनेकों अधिकारियों कर्मचारियों की दुकानों पर ठेकेदारों के साथ साझेदारी किसी से छुपी नहीं। अवैध शराब बिकवाने में संरक्षण देने में पुलिस के साथ यहीं के कर्मचारी अधिकारी होते हैं। हर बोतल अपनी मूल कीमत से 10-20रू ज्यादा

वसूल कर ही बेची जाती है। यहां भी पानी व लूट की कमाई का बोलबाला है। क्या हुआ, पूरे प्रदेश के वाणिज्य कर के 80 वृत्तों की 176 टीमों ने पटाखा व्यवसायियों उद्योगों पर छापा डालकर 3 दिन में मात्र रु 5.59 करोड़ की वसूली की। जबकि अकेले इंदौर के राऊ में, हातोद देपालपुर उज्जैन के बड़नगर मे 200 से ज्यादा, व पूरे मप्र के लगभग 1000 से ज्यादा पटाखा उत्पादक लगभग 500 करोड़ की टैक्स चोरी करते हैं। जबकि पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा पटाखा विक्रेता लगभग के 1000 करोड से ज्यादा की टैक्स की चोरी करते हैं।बिना ज्ञान और अनुभव के 176 टीमों ने 3 दिन में मात्र रु5.59 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी यह लोकेश जाटव आयुक्त की उपलब्धि थी। जानबूझकर एंटीवर्जन की टीमों को 18 महीने से छापा मारने, वाहनों को पकड़ने धारा 68 और 71 में अधिकार नहीं दिया जा रहे। क्योंकि आयुक्त लोकेश जाटव का आरोप है कि उनमें अहंकार आ गया है। और वह भ्रष्टाचार करते हैं।

आपको अपने काम से मतलब है। या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन खाकर प्रधान सचिव दीपाली रस्तोगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आयुक्त लोकेश जाटव अपने ही स्टॉफ पर आरोप लगाकर पूरे विभाग का मनोबल तोड़ने का षड़यंत्र कर राजस्व की हजारों करोड़ प्रतिमाह की हानि कर रहे हैं।

दूसरी तरफ हास्यास्पद यह है कि जिस धारा 68, 71 में अधिकार देने की शक्तियां संयुक्त आयुक्त के पास में हैं। उन पर जबरदस्ती बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कहने पर घोर भ्रष्ट दीपाली रस्तोगी जो 6 साल से एक ही विभाग में डटी हुई है। उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। जबकि वहीं केंद्र सरकार कासीजीएसटी विभाग खुले में 24 घंटे ना केवल वाहनों की धरपकड़ करते हैं।

मोटी वसूली भी करते हैं और टैक्स भी पूरा जमा करवाते हैं।

उसके बाद में भी उनकी इंफोर्समेंट की टीम भी गोदामों दुकानों उद्योगों पर लगातार छापे मारकर कई गुना ज्यादा वसूली करती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधान सचिव मंत्री जगदीश देवड़ा, आयुक्त लोकेश जाटव को इन सब से कोई मतलब नहीं।

उसे तो जनता को कैसे लूटना है। हर सरकारी काम की शुल्क 10 गुना तक बढ़ाकर जनता का खून कैसे पीना है। की व्यवस्था में लगा हुआ है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेजॉन वॉलमार्ट अदानी अंबानी टाटा बिरला आईटीसी युनिलीवर सब महीना दे रही हैं। छोटे व्यापारियों उद्योगों दुकानदारों को टैक्स के चक्रव्यूह में फंसा कर खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।इसे कैसे हो और कोई क्यों समझेगा।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2002 में ग्रेट गेलियन को प्रदूषण के करण बंद कर दिया था। जिस पर विवेक द्विवेदी तत्कालीन आर ओ ने ताले ठोक सदा के लिए बंद कर दिया व विद्युत विच्छेदन कर दिया था। तो आबकारी प्रधान सचिव दीपाली रस्तोगी ने उसको बाटलिंग का ठेका भरे कोरोना काल में अवैध रुप से कैसे व कितना धन हजम कर दिया। जब वह केड़िया की ग्रेट गेलियन डिस्टलरी बंद कर दी गई। तो उसमें उत्पादन कैसे, व क्यों हुआ? स्वाभाविक है। अवैध उत्पादन होने के साथ राजस्व की भी अरबों की हानि की गई। साथ ही उसके अवैध उत्पादन की बिक्री भी बाजार में, गुजरात में हुई।

दीपाली रस्तोगी के रहते हजारों करोड़ के घोटाले आबकारी में हो। रहे हैं। राजस्व की हानि कर चोरीवाणिज्य कर, आबकारी में रोकने की अपेक्षा ऊपर से शिवराज धन हजम कर घी पी रहा है। सरकार चलाने केवल अक्टूबर-नवंबर में 4000 करोड रुपए का लोन बाजार से 10% से ज्यादा की दर पर उठाया गया।

पूरा देश लाक डाउन में था लोग रोज़गार को तरस रहे थे विनय केड़िया कीमध्यप्रदेश डिसलरी शराब उगल रही थी!

देश के प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश सरकार और विनय केड़िया की ग्रेट गेलियन डिसलरी की जाँच सी बी आई, ई डी से करा ले तो प्रमाणित हो जायेगा गुजरात शराब बड़े पेमाने पर ईस फेक्टरी से शराब लाँक डाउन में गयी! लोग लाँक डाउन में घरों में दुबके थे मज़दूर भूख प्यास से बिलख कर रोज़ी रोटी को तरस रहे थे और मध्यप्रदेश सरकार की मेहरबानी से ग्रेट गेलियन शराब उगल रही थी ! मध्यप्रदेश की प्रमुख सचिवदीपाली रस्तोगी की भूमिका पर सवाल उठ रहे है की जब तीन आई ए एस ने जाँच कर फेक्टरी सील की थी तो खुली केसे! जिस फेक्टरी में अनियमितता पायीं गयी उसे पूरे प्रदेश के देशी शराब की ठेके क्यों दिये? जबकि ग्रेट गेलियन की पूरे प्रदेश में आपूर्ति की षमता ही नही है ! जनवरी 2020 माह में ग्रेट गेलियन लिमिटेड 160 कंचनबाग़ के बिजली बिल की खपत 43000 यूनिट थी और बिल 848700, फ़रवरी 2020 में 35250 यूनिट खपत थी और बिल 802241 था बिजली का बिल 2020 मार्च में 1266640हो गया 2020 अप्रेल में जब देश में लाँक डाउन सर चड़कर बोल रहा था तब 151600 यूनिट बिजली की खपत हुयी और बिजली बिल1038909आया ! ताज्जुब जब हुवा जब मध्यप्रदेश सरकार ने देशी की आपूर्ति के लिये ग्रेट गेलियन पर भरोसा जताया उसके बाद जो बिजली की खपत हज़ारों यूनिट में थी वह वर्ष 2021 अक्तूबर माह में 5000 यूनिट पर सिमट गयी जिसका एवरेज बिल आठ लाख रुपये माह से कम नही आता था वह563165पाँच लाख पर केसे सिमट गया!जबकि ग्रेट गेलियन परे प्रदेश में देशी की आपूर्ति कर रहा क्या चोरी की बिजली से फेक्टरी संचालित हो रही थी या पूर्ति कही और से हो रही थी!

हम भ्रष्टन के, भ्रष्ट हमार।
लूटमार का चलने दो खुलकर व्यापार।
अंतिम वर्ष है चुनाव का।
हमें सत्ता मिलने का नहीं एतवार।

अद्भूत

गणित में कोई भी संख्या 1 से 10 तक के सभी अंकों से नहीं कट सकती, लेकिन इस विचित्र संख्या को देखिये..!

दरअसल, सदियों तक यह माना जाता रहा था कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे 1 से 10 तक के सभी अंको से विभाजित किया जा सके। लेकिन रामानुजन ने इन अंकों के साथ माथापच्ची करके इस मिथ को भी तोड़ दिया था। उन्होंने एक ऐसी संख्या खोजी थी जिसे 1 से 10 तक के सभी अंकों से विभाजित किया जा सकता है। यानी भाग दिया जा सकता है। यह संख्या है 2520, संख्या 2520 अन्य संख्याओं की तरह वास्तव में एक सामान्य संख्या नही है, यह वो संख्या है जिसने विश्व के गणितज्ञों को अभी भी आश्चर्य में किया हुआ है। यह विचित्र संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक अंक से भाज्य है। ऐसी संख्या जिसे इकाई तक के किसी भी अंक से भाग देने के उपरांत शेष शून्य रहे, बहुत ही असम्भव/दुर्लभ है - ऐसा प्रतीत होता है।

अब निम्न सत्य को देखें :

2520 ÷ 1 = 2520
2520 ÷ 2 = 1260
2520 ÷ 3 = 840
2520 ÷ 4 = 630
2520 ÷ 5 = 504
2520 ÷ 6 = 420
2520 ÷ 7 = 360
2520 ÷ 8 = 315
2520 ÷ 9 = 280
2520 ÷ 10 = 252

महान गणितज्ञ अभी भी आश्चर्यचकित है : 2520 वास्तव में एक गुणनफल है 7 x 30

साप्ताहिक समय माया

मप्र जल संसाधन लूट डकैती विभाग

हजारों करोड़ की योजनाएं बनाई जिसमें 65-70% कमीशन

(समय माया)

चाहे प्रदेश का हो या देश का सबसे ज्यादा तकनीकी भ्रष्टाचार के इंजीनियर होते हैं मेरे पास कहानियां तो बहुत सारी हैं। चुनावी साल मैं सारे सत्ता के मंत्री मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी शासकीय विभागों में बैठे भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी लूट के हर दांव आजमा, हर षड़यंत्र कर रहे हैं।

सांवेर का विधायक और वर्तमान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जिसने कांग्रेसमें भी रहते हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार लूट शुद्ध के नाम पर विशुद्ध लूट का युद्ध किया। जल संसाधन विभाग में जिसके लिए शिवराज पर भारी दबाव डाला गया और इसी के लालच के चलते उसने अपनी ही मातृदल कांग्रेस की सरकार को गिरा कर भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गया। वैसे एक तरफ तो सरकार पेट्रोल डीजल गैस शराब में दुनिया में सबसे ज्यादा कर लूटने के बाद में भी कंगाल होने का नाटक कर रही है। जबकि उसके पास एसजीएसटी से 18 महीने में लगभग 70हजार करोड रुपए की आय होने के साथ उसको केंद्र से भी सीजीएसटी व आयकर का विभिन्न योजनाओं में हिस्सा मिल चुका है। दूसरी तरफ प्रदेश के जल संसाधन विभाग में 80% योजनाएं अब जल उद्वहन की बनाई जा रही है जिसको उसने 1980 में त्याग दिया था क्योंकि अधिकांश जल उद् वहन परियोजनाओं में उसकी आधारभूत आवश्यकता बिजली की होती है। सिंचाई के लिए अत्यधिक महंगी पड़ती है बंद कर दी थी पर भ्रष्टाचार और मोटी कमाई के चलते पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ की योजनाएं बनाई गई हैं जिसमें 65 70% एकमुश्त पाइप लाइनों, इलेक्ट्रिक मोटर पंपों, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के सामान की खरीदी मैं वैसे अच्छी गुणवत्ता और स्तर की एमएसस्टील स्टील की 6', 1', 50 सेमी, 1मी, 2मी, 2.5मी 3मी, आदि की अच्छी कंपनी की पाइप खरीदी में, यही हाल मोटर पंप पुरानी सामग्री खरीदी में मात्र 3 से 5% तक का ही कमीशन होता है। परंतु अब चारों तरफ चीनी माल और कंपनियों का बोलबाला है। वे अपना माल बेचने के लिए खरीदार की हसरत को पूरा करते हुए मोटा कमीशन और मोटा भी बना कर दे देती हैं जो ना केवल पाइपलाइन मोटर पंप ओं इलेक्ट्रिक सामग्री तार खंभों सब स्टेशन ट्रांसफार्मर तक में सीधा कमीशन मिलता है। और माल की डिलीवरी व गोदाम में दिखाने पर उसका शासन भुगतान कर देता है। इससे सीधी बंदरबांट उपयंत्री सहायक कार्यपालन अधीक्षण यंत्री से लेकर मुख्य प्रमुख प्रमुख सचिव और मंत्री तक पहुंच जाती है बाकी 30% तक का कार्य, बड़ी टंकी, या तालाब बनाने, खुदाई लाइन बिछाने खेतों तक पहुंचाने में मेजर, मीडियम, माइनर स्तर की पाइप लाइनों, वितरणी उपवितरणी आदि के माध्यम से जल संग्रहित कर खेतों तक त्वरणवेग

से वितरित किया जाता है। जिसका पैसा किसानों से वसूल किया जाता है। दूसरी तरफ सीधा पर घोर भ्रष्ट जालसाज वर्तमान में बैठा प्रमुख अभियंता एमएस डावर जिसका अधिकांश समय सहा., कार्य. अधी. यंत्री, रहते हुए धार में गुजरा उसके वहां पर किए गए कार्यों से उसके भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कि वह किस प्रकार से भ्रष्टाचार ठेकेदारों को सर पर नाच कर भ्रष्टाचार को अंजाम देता रहा। फिर जब वह इंदौर में मुख्य अभियंता रहा तब भी सारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार होने के साथ-साथ बांधों, तालाबों के साथ उनकी नहरों की खुदाई, काक्रीटिंग में भी डीपीआरके अनुसार कम व स्तरहीन काम हुआ। जानबूझकर ओगी फाल बनाकर करोड़ों रुपए हड़पा गया। किसके काल में चंबल बेतवा कछार भोपाल में 17-18 में 26, 18-19 में 21 और 19-20 में 15 योजनाएं, केन कछार सागर में 17-18 में 18-19में 16, 19-20 में 3, गंगा कछार रीवा में 17-18 में 1,18-19 में 0, 19-20 में 5, नर्मदा ताप्ती कछार में 17-18 में 23, 18-19 में 27, 19-20 में 21, बाणगंगा कछार सिवनी में 17-18 में 11, 18-19 में 9, 19-20 में 9, उज्जैन में 17-18में 32, 18-19 में 21, 19-20 में 13 योजनाऐं, होशंगाबाद में 19-20 तक 23

सबसे ज्यादा लूट जल संसाधन ने नर्मदा घाटी मची है। सक्षम इंजीनियर उपयंत्री सहायक, कार्य पालन, अद्दीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता जो सब मोटा प्रभार देकर प्रभारी बना बैठा दिये हैं। लगभग 50हजार करोड़ रुपए की लिफ्ट इरिगेशन की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बन रही हैं। जिस लिफ्ट इरीगेशन के बारे में 1970 में ही बिजली खर्च, उच्च लागत व रखरखाव के कारण विभाग ने हीं अनुपयुक्त माना था।

अकेले देवास में उपयंत्री स्तर का जादौन कार्य पालन यंत्री के प्रभार में बैठा दिया है। जबकि वहां हाटपिपल्या लिफ्ट इरीगेशन की रू 3793 करोड़ की 21% कम दरों पर परियोजना का काम शुरू हो गया। जबकि उप, सहायक कार्यपालन व अधीक्षण यंत्री स्तर के कोई भी सक्षम यंत्री नहीं है सब प्रभार में बैठाये हैं। जिनके पास 50 करोड की खुशी परियोजना को बनाने चलाने का अनुभव तक नहीं। चल रही है।

एलएंडटी कंपनी ने आते ही साथ खेल दिखाना शुरू कर दिया। उसने विभाग के सर्वे व बनाई डीपीआर को अलग कर पुनः सर्वे करवाने के नाम 5% कुल परियोजना का धन वसूल कर अर्थात 200 करोड़ का बिल कार्य शुरू करने से पहले ही थमा दिया।

जनता से पेट्रोल-डीजल गैस व अन्य सरकारी सेवाओं में, शिक्षा, परीक्षा फीस के नाम में लूटे हुए पैसे की कैसी बंदरबांट की जाती है उसका एक छोटा सा नमूना है।

वही हाल शामगढ़ सुवासरा लिफ्ट इरिगेशन में भी कंपनी ने नीचे ग्रुप अटेंडर लेकर 205 करोड़ के एक्सटेंशन की मांग की है वहां बैठा घोर धूर्त भ्रष्ट सांखला जो मोटा पैसा देकर हर बड़ी परियोजना में लूट और भ्रष्टाचार के लिए पहुंच जाता है। कार्यपालन यंत्री के प्रभार में है। इसीलिए

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हरामखोर जरूरत से ज्यादा होशियारी व बत्तमीजी दिखलाता है। जनता से लूटे पैसे की ये मंत्री तुलसी सिलावट मुख्यमंत्री शिवराज व इंजीनियरों की फौज कैसे लूटती और लुटाती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति शिव बाबा बैराज नेपानगर सामान्य बुरहानपुर 200 हेक्टेयर 348 लाख 90 हजार, ढोंड बैराज नेपानगर सामान्य बुरहानपुर 260 हेक्टेयर 452 लाख 35 हजार, रिक्षिखो बैराज खातेगांव सामान्य देवास 180 हेक्टर 2 करोड़ 63 लाख 63000, मेहत गांव बैराज सेंधवा आदिम जाति बड़वानी 240 हैकटेयरनिर्माण लागत 284 लाख 71हजार, मेल्या बैराज सेंधवा आदिम जाति बड़वानी 225 हेक्टेयर 301 करोड़ 94 लाख, सनफ़ देव बैराज सेंधवा आदिम जाति बड़वानी 317 लाख 90 हजार बांदा बैराज धार 245 हैकटेयर 428 लाख 48 हजार घटबोरी बैराज बाघ आदिम जाति धार 202 हेक्टेयर 315 लाख 14 हजार खड़खड़ी अलीराजपुर आदिम जाति 180 हैकटेयर 176 लाख 34000 प्रतापपुर कट्ठीवाडा 190 हैकटेयर316 लाखा 61000 मिशन बहराइच जोबट आदिम जाति अलीराजपुर 570 हेक्टेयर रु. 859 लाख 54 हजार सज्जनपुर बैराज कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर 385 हैकटेयर 582 लाख 94 हजार

वल्लभ भवन जल संसाधन मंत्रालय 19 जुलाई 22 लघु सिंचाई परियोजना नया मालाहेड़ा नीमच 155 हैकटेयर निर्मला का 270 भाग सरस्वती 450 लाख 25 हजार जामनेरी बैराज शाजापुर 200 हैकटेयर 280 लाख 31

हजार, पेवची बैराज शाजापुर 200 हैकटेयर 276 लाख 46000, लाला खेड़ी सुजालपुर शाजापुर 200 हेक्टेयर 299 लाख 5 हजार, घटवास रतलाम 205 हेक्टेयर 357 लाख 15000 चिमली बराज सांवेर इंदौर 155 हैकटेयर देखो 265 लाख 33 हजार नवलपुरा बैराज गोगंवा आदिम जाति खरगोन 225 हेक्टयर 391 लाख 19 हजार मांगलिया बैराज कम क्रॉसवे सांवेर इंदौर 195 हेक्टेयर रू. 336 लाख 81000 है! देवास संभाग में सोनकच्छ के 11 करोड़ के बैराज अनखेलि, खोकरिया, गोला बैंरेज के कार्यों की डीपीआर से जांच की जानी चाहिए। सोनकच्छ का एसडीओ चा वैसे भी घोर भ्रष्ट जालसाज होने के साथ केवल वसूली में लगा रहता है काम पर पकड़ नहीं ठेकेदारों से काम जैसा उंहोने कर दिया। कमीशन लेकर बिल पास कर दिए जाते हैं।

चंद केशर की लाइनिंग का 18 करोड़ स्वीकृत हुआ था। जिसमें से रु. 8 करोड़ खर्च कर दिया गया है। जबकि वहां पर भी काम अधिकांश कागजों पर किया गया और बरसात का इंतजार किया जा रहा था। ताकि बरसात आए तो दिखा दी जाएगी सब बह गया।और वह काम कागजों कर किया दतूनी नहर जो 40 किमी लंबी है।

जो पहले से ही काफी स्तरहीन तरीके से निर्मित की गई हैं। और बिना तल मिलाये जिसे कहीं पर बेड लेवल 2 फुट कहीं पर 3 फुट है। इसके बारे में लगातार 18-19 से समय माया समाचार पत्र प्रकाशित करता रहा है और अनेकों नहर के तल के,ऊपर की चौड़ाई के साइट से फोटो खींचकर डाले गए थे। तब भी लगातार छापा व बताया भी गया। अब लगातार हर वर्ष टूट-फूट आदि के मरम्मत के कार्यों के ठेके दिए जाते हैं पर अधिकांश कार्य कागजों पर ही संपन्न कर पैसा हजम कर लिया जाता है इस वर्ष भी वही हुआ। वर्तमान में देवास संभाग में हाटपिपलिया प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जिसे एनवीडीए को करना चाहिए था। देवास संभाग को सौंप दिया गया है यहां सक्षम स्टाफ ही नहीं है और जिस ढीले कार्यपालन यंत्री जादौन को बैठाया गया है बेशक मोटा कमीशन लेकर प्रभार दिया गया है और सारे जितने भी एसडीओ हैं वह भी सब मोटा प्रभार देकर बनाए गए प्रभारी हैं स्वाभाविक है उन्हें काम से नहीं कमीशन खोरी से मतलब है जहां तक संभागीय कार्यालय में बैठे स्टाफ का सवाल है। तो अधिकांश अनुभवी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद बचा हुआ 20% स्टाफ काम जानता ही नहीं। और यहां तक की संभाग की कार्य रोकड़ बही भी घर पर ले जाकर पैसे देकर अन्य अनुभवी सेवानिवृत्त व्यक्तियों से लिख वाई जाती है। इस बात की सत्यता की पुष्टि संबंधित बाबू के घर पर किसी भी शनिवार रविवार को छापा मार घर पर रखी केशबुक पकड़ी जा सकती है। बेहतर होगा कि लगभग 4000 करोड़ के हाटपिपलिया प्रोजेक्ट को जो एलएनटी को ठेका दिया गया है। उसकी निगरानी देवास संभाग से लेकर पुनः नर्मदा घाटी को दे दी जानी चाहिए।क्योंकि यह कार्य जानबूझकर घोर भ्रष्ट मंत्री तुलसी सिलावट ने मोटे कमीशन के लिए एनवीडीए से लेकर जल संसाधन संभाग देवास को दे दी। जबकि वहां ना तो अनुभवी स्टाफ है और सारा तकनीकी कार्यपालन यंत्री से लेकर उपयंत्री तक सभी प्रभारी बैठा ले गए हैं या नए नियुक्त किए गए अनुभवहीन उपयंत्री कार्य देख रहे हैं स्वभाविक है कि जिन्होंने मोटा पैसा दिया है वह वसूली पर ध्यान रखते हैं। एल एंड टी ने ठेका मिलने के साथ ही विभाग के सर्वे को नकार पुनः सर्वे करने के नाम 10 करोड़ का बिल ठोक दिया। उसको भी कार्यशील पूंजी और मशीनों के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया जिसमें से मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री अभियांत्रिकी सदस्य नर्मदा घाटी प्रमुख अभियंता जल संसाधन ने अपना कमीशन बटोर लिया था।

जनता से पेट्रोल डीजल गैस वाह 1500 से ज्यादा वस्तुओं पर धोखे गए भारी-भरकम जीएसटी से की जा रही लूट को हजारों करोड़ के काम दिखाकर कैसे मोटा कमीशन बटु आजम किया जा रहा है यह देवास संभाग की हाटपिपलिया प्रोजेक्ट से जिसमें इंदिरा सागर बांध से जल उदवहन कर देवास की हाटपिपलिया तहसील और उसके आसपास के लगभग 80000 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। वैसे भी जल संसाधन विभाग में 1970 से ही लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्कोर अत्यधिक महंगे होने और बिजली की भारी खपत के कारण बनाना ही बंद कर दिए थे परंतु मोटे कमीशन के चलते नर्मदा घाटी और जल संसाधन विभाग दोनों में रु. 1 लाख करोड़ से ज्यादा के 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट केवल लिफ्ट इरिगेशन के केवल कमीशनखोरी के लिए चलाए जा रहे हैं। जो भविष्य में सफेद हाथी सिद्ध होंगे।

नगर निगम पालिका या डकैत जालसाजों के अड्डे, जनता से व जनधन की हजारों करोड़ की लूट

हजारों करोड़ की बर्बादी चारों तरफ खुदी ऊबड़-खाबड़ सड़कें

सूचना के अधिकार में हरामखोर व्यर्थ तर्क देंगें जानकारी नहीं... 18 साल बाद भी वेवसाइट पर भ्रष्टाचार छुपाने जानकारी अपलोड नहीं...

(समय माया)

इंदौर नगर निगम में अधिकांश वर्षों से जमे घोर जालसाज डकैत अधिकारियों इंजीनियर, डॉक्टर, निरीक्षकों, बाबू रूपी गिद्धों का बसेरा है। जो पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियां भू कॉलोनी माफिया ठेकेदारों के सारे पर नाच कर एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार की सौ से ज्यादा योजनाओं में हजारों करोड़ का धन हजम करते हैं। तो दूसरी तरफ पग मार्गों सड़कों पर बैठे, ठेले, गुमटी वाले सब्जी-भाजी, पानी पुरी, चाट पकोड़े बेचने वाले गरीब विक्रेताओं को लूटने से लेकर, झुग्गी बस्तियों, झोपड़ियों चालों,

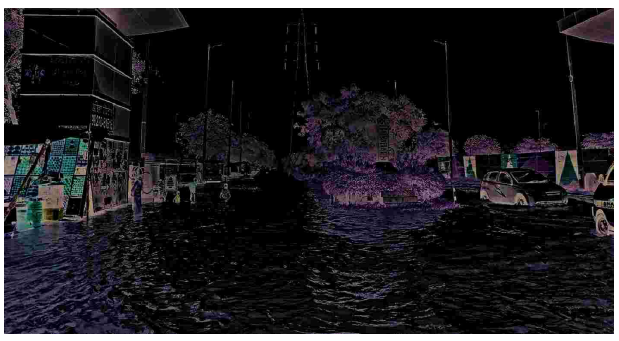

मकानों, बहु मंजिला भवनों, किराए से रहने वाले गरीब निवासियों को कचरे के नाम पर लूटने और फिर उसे कचरे में से बेचने योग्य प्लास्टिक पन्नी, बोतले इलेक्ट्रॉनिक कचरा व अन्य सामान निकाल कर बेचकर खा जाने वाले सफाई कर्मियों की डकैती चलती रहती है।

बाजारों में दुकानदारों, बस्तियों औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले चलने वाली फैक्ट्रियों में से नगर निगम की गाड़ियां कचरा बटोरने के साथ तत्काल ही उसमें से कचरा छांट बीन कर कबाड़ियों पॉलिथीन वालों को बेच दिया जाता है। पहले जब यह कचरा घरों फ्लेटों भवनों दुकानों बाजारों से वाहनों के माध्यम सेएकत्रित करने की व्यवस्था शुरू हुई थी तब कचरा गाड़ियां दिन भर में हर 1-2 घंटे में चक्कर लगाती थी। और उस समय लगभग शहर भर में 500 से ज्यादा गाड़ियों में, 200 से ज्यादा मिनी ट्रकों, 100 से ज्यादा बड़े ट्रकों में, जिनकी खरीद में मोटा कमीशन मिला था और महापौर निगम आयुक्त कलेक्टर कमिश्नर आदि को 10से ज्यादा कारें गिफ्ट की गई थी। इन कचरा गाड़ियों पर डीजल पेट्रोल पर रू. 6 करोड़ का खर्च होता था। व रू. 1 करोड़ का रखरखाव पर खर्च होता था। जिसका तब 20% पैसा हजम किया जाता था। और अब पेट्रोल डीजल का 70% पैसाऔर मेंटेनेंस काभी 80% पैसा कागजों पर खर्च दिखाकर हजम कर लिया जाता है पेट्रोल डीजल बैच ने लूटने के मामले में गाड़ियों के ड्राइवर भी अपना खेल दिखाते रहते हैं। कचरा बटोरने की रसीद अलग से भी महीने की 80 से रु. 300 तक की 50% नकली रसीदें भी कटती है। ऊपर से कचरा गाड़ी वाले भी पैसे भी लेते हैं। जबकि जो ऊपर से पैसा नहीं देतेउन्हें गीला सूखा कचरे के नाम पर सफाई कर्मी बदतमीजी के साथ प्रताड़ित करते रहते हैं।

इसके साथ ही हर बार त्योहार पर इनाम के नाम पर घरों से रू. 50 से बड़े भवनों दुकानदारों से, फैक्ट्री उद्योगों से 500 से रु. 5000 तक वसूली लिए जाते हैं इस प्रकार सफाई कर्मी भी साल भर में जनता से रुपए एक अरब तक वसूली कर डालते हैं। जबकि वहीं कचरा नगर निगम इंदौर अधिकृत तौर पर रु. 10 किलो बेचती है जबकि 21 से 25 रु किलो तक में बैंच कर मोटी कमाई की जा रही है। जबकि सन 2006 में ही पूरे शहर के कचरे को उठा रुपया 10 प्रति किलो निगम को देकर बिजली बनाकर बैचने की तैयारी थी। परंतु वह प्रोजेक्ट इसलिए नहीं माना गया कि इनको कुछ

नहीं मिलता अब उनके खास आदमी को पूरा सैकडों करोड़ का 16000 टन गैस का प्लांट जो घोर भ्रष्ट जालसाज मनीष सिंह के समय में 30% कमीशन पर बनाया गया। दे दिया गया है।

सफाई कर्मियों को विकसित 23 साल से लिख रहा हूंकीहाथ में हैंडग्लव्स मास्क पैरों में गम बूट देने के साथ साल भर की दो साधारण ड्रेस और रेनकोट और व्हाट्सएप शीत ऋतु के लिए गर्म कपड़े दिए जाने चाहिए वह पैसे निकाले जाते हैं ऊपर की ऊपर आजम कर लिए जाते हैं इसके साथ ही जब सफाई कर्मियों को 30 साल हो चुके हैं पर उनका नियमित नहीं किया जा रहा पेंशन की सुविधा नहीं। बूढ़े होने पर इन्हें कौन दो वक्त की रोटी देगा?

फिर अधिकांश सफाई कर्मी नगर निगम के पार्षदों अधिकारियों की ठेकेदारी में काम करते हैं। उनके वेतन में से भी ठेकेदार पैसे काट लेता है। बेशक ठेकेदार सौ कर्मचारियों का पैसा लेता है और 40% ही काम करते हैं 60% में से निगमायुक्त, उपायुक्त सहायक एक आयुक्त महापौर, सफाई व स्वास्थ्य समीति, पार्षदों, दरोगा, आंचलिक अधिकारियो, से बिल पास करने वाले बाबुओं तक सबके हिस्से की बंदर बांट होती है। दूसरी तरफ सफाई से संबंधित झाड़ू फिनायल व अन्य सैकड़ों प्रकार की सामग्री की खरीदी में भी अधिकांश के बिल कागजों पर ही खरीदी की जाकर हजम कर लिया जाता है जो हर महीने 5 से 10 करोड रुपए होता है। पहले कचरा गाड़ियों की तरह सफाई भी सुबह दोपहर व रात में भी होती थी पर उसके भी बिल बनाकर हजम कर ले जाते हैं। जून 22 के बाद पूरे शहर की अधिकांश सड़कों को नाली बिछाने के नाम पर खोद न केवल बिना टोप्पो व कांटूर नक्शों की ठोस नीति के साथ बस्ती के रहवासियों की संख्या जल उपभोग और निकासी की मात्राके साथ वर्षा के निकासी की व्यवस्था व नीति के बिना पार्षदों और अधिकारियों ने मोटी कमाई के लिए मनचाहे तरीके से नालियां खोदने बिछाने के कार्यों में पिछले 23 वर्षों में लगभग 5000 करोड रु जिसमें विश्व बैंक एडीबी का ऋण जेएनआरयुएम व वह अनेकों योजनाओं का धन बर्बाद करने के उपरांत भी जल निकासी की ढंग से व्यवस्था न होने के कारण थोड़ी सी वर्षा में ही चारों तरफ सड़कें बाढ़ के जल से नालों व तालाब में परिवर्तित हो जाती है। जिसकी फोटो और परेशानी की कहानियां रोज दैनिक समाचार पत्रों में छपते हैं।

परंतु घोर भ्रष्ट जालसाज मोटी चमड़ी के बेशर्म ठेकेदारों, मुख्य, अधीक्षक, कार्यपालन, सहायक और सब इंजीनियर पार्षदों अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे ही भू माफियाओं कॉलोनी माफियाओं जिन्होंने शहर की तीन नदियों के जल संग्रहण व बहाव के साथ उनमें मिलने वाले नालों की, नजूल की 50% भूमि पर कब्जा करअपनी बहू मंजिला इमारतें कालोनियां खड़ी कर दी है। उनकी मोटी कीमत वसूल करने व मोटा पैसा खर्च कर सफाई का पुरस्कार ले आते हैं। और अपने सारे पाप ढांक लेते हैं। हरामखोर जालसाज कलेक्टर कमिश्नर महापौर से लेकर नीचे सभी ने क्योंकि मोटा पैसा हर कदम पर अरबों में बंदर बांट की है। तो सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर यह मक्कार दोस्तों की फौज पांच पांच पेज की दलिले देती है पर 18 साल गुजर जाने

के बाद में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिए 17 बाद में आठ बिंदु और जोड़े गए 25 बिंदुओं की जानकारी 18 साल बाद भी अपलोड नहीं कर सके और ना करेंगे क्योंकि हर साल लगभग पूरे निगम में 5000 करोड रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया जाता है।

नगर निगम पालिकाओं को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारियां डालनी चाहिए थी। पर हर कदम फैले भ्रष्टाचार लूट खसोंट डकैती करने के कारण वहां बैठे जालसाज आयुक्त उपायुक्त सहायक आयुक्त से लेकर सारे इंजीनियर डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी दरोगा सब घोर भ्रष्ट होने के कारण नहीं डालते। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वहां बैठे डकैतों की फौज औचित्यहीन दलीलें जरूर देगी। परंतु भ्रष्टाचार छुपाने जानकारी नहीं देगी वहां बैठे भारतीय पकड़ना सेवा के अधिकारी जोहर भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा बलते हैं सारी अपीलों को रद्द कर देते हैं। हर साल अकेले इंदौर में, पिछले 18 वर्षों में लगभग 50000 हाथ ठेले, अर्थात 9 लाख हाथ ठेले तोड़, हर वर्ष 2 लाख ठेले व पग मार्गो पर सब्जी व अन्य सामान बेंच ने वालों का माल फेंका लूटा जब्त किया ताकि शॉपिंग मॉल से मिलने वाले कमीशन के कारण निगम के कर्मचारियों अधिकारियों ने तोड़े, लूट कर शापिंग माल वालों को फायदा पहुंचाया। इसके विपरीत हर दिन 2000 ठेले वालों से 5 हजार प्रति ठेला हर माह, पूरे शहर में 60 हजार ठेले वालों से रु 30 करोड़ प्रति माह की वसूली निगम के लोगों द्वारा की जाती है। पुलिस भी हर दिन पूरे शहर के 60 हजार ठेले वालों से नगद व फल, फूल सब्जी व सामग्री के रुप में रू20 लाख वसूली करती है। नगर निगम के सुकरों का सवाल जहां तक है, तो पॉलीथीन, कचरा, गंदगी के नाम वसूली का खेल अलग चलता है। सड़कों पर खड़े 99% ठेलों, छोटे दुकानदारों को पुलिस व निगम के जनकार्य की सड़क, सफाई दरोगा की, पालीथीन की पर्यावरण, खाद्य में गंदगी के नाम खाद्य विभाग के गिरोह को धन चुकाना होता है। इसका भी मासिक हिसाब करोड़ों में होता है।

बेशक हिस्सा सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सहायक आयुक्त निगमायुक्त पार्षदों से महापौर तक पहुंचता है। यथार्थ मैं ठेले वाले इन के दम पर नहीं दिए ठेले वालों के दम पर मोटा धन लूटकर पलते हैं। बेशक इसकी बारी खोजबीन में तो और भी घिनौने तथ्य सामने आएंगे। यही कहानी हर गांव कस्बे शहर से लेकर पूरे देश के हर जिलों महानगरों तक की है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा घी बर्बाद हो रहा यूरोप खाड़ी देश

पेज 1 का शेष

आखिर यूक्रेन को उकसाकर उसे नाटो में अपनी गुंडागर्दी में शामिल कर और रूस को चारों तरफ से घेरने और कमजोर करने के मन्सूबों को सफल बनाकर उसके तेल गैस यूरेनियम अन्य प्रकार के खनिज पदार्थों पर कब्जा कर गुलाम बनाया जा सके। यह वही षड्यंत्र कार्यों अमेरिका है जिसने सोवियत संघीय गणराज्य रूस को 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव को खरीद कर उसके 27 टुकड़े कर दिए उसमें यूक्रेन भी एक राज्य है। जिसके राष्ट्रपति घोर लालची जेलेस्की जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मोटा धन खिला कर चालों में फंसकर नाटो में शामिल करने के लिए तैयार किया और यही नाटो में शामिल करना रूस को नागवार गुजरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को समझाया धमकाया पर अमेरिकी धन के आगे वह सूअर का पिल्ला रूस की नहीं माना और रूस को आक्रमण करने के लिए विवश किया। 25 फरवरी 2022 से लगातार रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अमेरिकी सूअर उसमें लगातार हथियार गोला बारूद विमानों ड्रोन की आहुति डालकर उस युद्ध को भड़का रहे हैं। अभी भी पुतिन उसे अपने देश का हिस्सा ही मानकर आक्रमण में संयम बरत रहा है। बेशक रूस को काफी नुकसान हुआ पर दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था पूरे यूरोपीय देशों को तेल गैस की सप्लाई से जो पूर्णता रूसी तेल गैस पर निर्भर थी कीमतें बढ़ाकर बेचने पर मजबूत हुई। रुस को चाहिए जितने भी देश नीच संकर अमेरिकी नाटो में शामिल है। उन सबको तेल गैस की आपूर्ति को हर 3 महीने में 10-10% बढ़ाता चला जाए। ताकि जर्मनी कनाडा स्वीटजरलैंड अमेरिका की व अन्य सभी देशों की जनता बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अपनी ही सरकारों के खिलाफ बगावत कर नाटो से अलग होने के लिए विवश करें साथी उन सभी यूरोपियन देशों कीआर्थिक कमर तोड़कर अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जानी चाहिए। वहां की जनता अपने देश की सरकारों को अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा यूक्रेन को हथियार देने शुरू होकर युद्ध रोकने के लिए विवश करें। बेशक अमेरिकी कंपनियां पुराने कबाड़ हथियार यूक्रेन पहुंचा कर भले ही खुश हो रही हों परंतु 20 महीने में यूरोपियन देशों की बढ़ती गैस होटल की कीमतों ने एक तरफ जनता को महंगाई की मार मारी तो दूसरी तरफ उन देशों के अर्थव्यवस्थाओं को भी चौपट किया यह सब कुछ अमेरिकी षड्यंत्रकारी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का परिणाम है जो पूरे यूरोप के देशों को बर्बाद कर रही है। अमेरिका को नष्ट करने आवश्यक है की रूस को चीन उत्तर कोरिया के साथ शामिल होकर आक्रमण कर देना चाहिए जहां तक नाटो का सवाल है तो शांति रखिए और देखते चलिए जिन देशों में अमेरिकी सेनाएं बरसों से वहां पड़ी रहकर वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के साथ वहां की जनता को गुलाम बनाकर उपयोग करने जनता पर उनके खर्च का भार लादकर लूटने अपनी सेनन को पालने के लिए जो अमेरिकी दवाब में बरसों से झेल रही है? तृतीय विश्व युद्ध शुरू होते ही जापान जैसे देश भी अपना 1945 का हिरोशिमा और नागास्की पर टपक गए परमाणु बम का बदला लेने अचानक पलट कर अमेरिका को खत्म करने में रूस चीन के साथ शामिल हो जाएंगे। अमेरिका के शिकार 80 से ज्यादा देश उसकी सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्षों से जो पाल रहे हैं वह भी अमेरिका के चंगुल से मुक्ति पाने सेनाओं को भगाने, अमेरिका का पलड़ा कमजोर होते ही पलट कर नष्ट करने पर तुल जाएंगे। अमेरिका के नष्ट होने से आने वाले 50 साल में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ीयां शांति से रह सकेंगी।

साप्ताहिक समय माया

जाना निश्चित, तो क्यों लगे हो मप्र की बर्बादी में

पेज 1 का शेष

जिसमें वन विभाग नदी नालों नहरों, बांधो, आदि की भूमि हजम करने वह माफिया कॉलोनी माफिया द्वारा कालोनी विकसित करने मैं भी हर साल पूरे प्रदेश में गांव से लेकर महानगरों तक हजारों करोड़ के घोटाले होते हैं। सारे पटवारी तहसीलदार एडीएम एसडीएम कलेक्टर होने हजारों करोड रुपए साल के भ्रष्टाचार जमीनों की खरीदी बिक्री नामांतरण

सभी भ्रष्टाचारियो को जो लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, ग्रामीण एवं शहरीय विकास, स्वास्थ्य, जनसंपर्क, महिला बाल विकास, परिवहन, पशु चिकित्सा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं स्वास्थ्य शिक्षा, मंत्रालयों आदि में ही हजारों करोड़ के खरीदी, सेवाएं देने, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं टीवी चैनल में प्रचार प्रसार में हीं हजारों को बर्बाद किए गए थे। कि भ्रष्टाचारियों को क्योंकि मोटा हिस्सा मिलता रहा इसलिए उन्हें उल्टे ही पुरस्कार बांटे गए। खनन घोटाले में जो निरंतर नर्मदा से 700 डंपरों से रु. 20000 प्रतिदिन अर्थात वर्ष के 300 दिन 18 वर्ष में 756000 करोड़ की रेती बेंच कर खा गए। 700x300x 20000x 18=75600000000 यह न्यूनतम है जबकि वर्तमान में 1 डंपर रेती की कीमत रू 40,000/- है। वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1000 डंपर से ज्यादा रेती ढो रहे हैं। जिससे यह आंकड़ा 15 लाख करोड रुपए के ऊपर चला जाता है। जबकि प्रदेश में लोहा तांबा अभ्रक, हीरे जैसे बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं।

बेशक देश विदेश में अनेकों होटल, अनेकों व्यवसाय, उद्योगी फार्म हाउस, फैक्ट्रियों में, पवन व सौर ऊर्जा में पैसा निवेश किया गया है। यही कारण है कि सन 2006, 7,8 मैं सौर और पवन ऊर्जा की खरीदी के छह रुपए प्रति मिनट के 18 उपाध्यक्ष हस्ताक्षर कर उनको हजारों करोड़ रुपये लुटाया जा रहा है जिसमें खुद का हिस्सा भी है जबकि उनसे एक पैसे की 1 यूनिट बिजली नहीं खरीदी जाती।

बेशक यह पैसा मोदी, अमित शाह को भी पहुंचा है। इसलिए तुम्हारे लिए कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार गिरवा कर सरकार बनवाई गई। क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा शिवराज ही केंद्र को दे रहा था। इसीलिए उसको चाह कर भी नहीं हटाया जा सका।

समाचार पत्र समूहों टीवी चैनलों का मुंह बंद करने के लिए 18 साल में लगभग 2 लाख करोड रु से ज्यादा पेट्रोल डीजल गैस शराब परिवहन टोल नाकों बिजली में, पिछले 7 सालों से 1500 से ज्यादा वस्तुओं पर ठोका गया जीएसटी में लूटा गया पैसा प्रसार माध्यम पर लुटाया जा रहा है।

अभी लगातार 3-4 महीने से जो सेकडों करोड़ प्रतिदिन के विज्ञापन टीवी चैनल पत्र पत्रिकाओं को पूरे देश और विदेश में दिए जा रहे हैं।

दूसरी तरफकर्मचारियों अधिकारियों के जानबूझकर सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की आड़ में सन 2016 से पदोन्नौतियां नहीं की जा रही है। जबकि उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है की पदोन्नतियों पर कोई रोक नहीं है। जहां तक स्थगन का सवाल है। जिन्हें सन 2002 में पदोन्नतियां दे दी गई थी। उन्हें पदोवनत न करने के लिए है। न कि पदोन्नतियां को रोकने के लिए है। आप चाहें तो पदोन्नतियां दे सकते हैं। परंतु अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने, भ्रष्टाचार से लूट करने, नियमों के विपरीत अपने खास अधिकारियों डॉक्टर इंजीनियर निरीक्षकों जो पूर्व से ही मंदबुद्धि कामचोर डकैत है ऐसे घोर भ्रष्टों से बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाकर मनचाही वसूली करने मनचाहा काम कर वाने के लिए मोटा प्रभार लेकर पूरे प्रदेश के सभी विभागों में प्रभार का खेल चलाया जा रहा है। जो केवल मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री प्रधान सचिव सचिव आयुक्त प्रमुख अभियंता संचालकों विधायकों सांसदों सबके लिए कमाई का लगभग 3 से 5000 करोड रुपए प्रतिवर्ष का स्रोत बना हुआ है और दूसरी तरफ ऐसे प्रभारी अधिकारियों कर्मचारियों को एक बार बड़े पद पर बैठा देने पर मनचाही मासिक वसूली का स्रोत भी बना रहता है आप अपने स्तर पर किसी भी प्रकार से डकैती डालो लूटो भ्रष्टाचार करो कोई कुछ नहीं बोलेगा। साथ ही सबकी मासिक किस्त पर वसूली होती रहती है जिसने भ्रष्टाचार से वसूली कर महीना नहीं पहुंचाया उसको वापस पुराने पद पर पदस्थ कर दिया जाता है। यह लूप पार्ट भ्रष्टाचार और डकैती का तांडव मध्य प्रदेश के सौ से ज्यादा विभागों में पिछले 7 साल से चलाया जाकर सैकडों करोड रु प्रति माह की वसूली की जा रही है।

यही कारण है की जल संसाधन विभाग में घोर भ्रष्ट जालसाज अधीक्षण यंत्री शिशिर कुशवाहा को मोती 25 करोड़ से ज्यादा की वसूली कर प्रभारी प्रमुख अभियंता बना दिया गया। यही हाल मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में घर भ्रष्ट फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले जिसकी जाति प्रमाण पत्र की जांच काफी लंबे समय से लंबित है। अधीक्षण यंत्री शालिग्राम बघेल जिसने इंदौर में अतिरिक्त परियोजना संचालक के पद पर रहकर 12 भवन निर्माण के संभागों से 2 साल में मुख्यमंत्री सीएम राइज स्कूल, स्कूलों कॉलेज न्यायालय भवन स्वास्थ्य चिकित्सालय भवन आंगनवाड़ी पंचायत कलेक्टर आदिम जाति जनजाति कल्याण छात्रावास भवनों आदि के निर्माण के लगभग 500 भवन निर्माणों में गुजराती व अन्य ठेकेदारों संभागीय यांत्रियों के साथ मिलकर आधे अधूरे स्तरहीन निर्माण में ही लगभग एक अब से ज्यादा की वसूली कर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता का पद सारे मुख्य अभियंताओं को पीछे छोड़ते हुए खरीद कर विराजमान करवा दिया गया। पूरे प्रदेश का विद्युत मंडल जल संसाधन के बाद तीसरे नंबर के इस कार्य विभाग में हर कदम पर भ्रष्टाचार से लूट का तांडव से वसूले धन से 10 करोड रुपए महीने की मासिक किस्त पर एक भ्रष्ट अधिकारी को पदस्थ कर दिया गया। यही हाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय में भी किया गया पूरे प्रदेश के सभी विभागों जिसमें गृह, ऊर्जा, वन, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी, पर्यावरण एवं आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी व ग्रामीण विकास, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खनन, राजस्व, पंचायत, आबकारी, परिवहन, रेशम संजनालय पशु चिकित्सा व डेयरी, कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास आदि मंत्रालय और इनके कार्यरत निगमों, पालिकाओं, कंपनियां, मंडलों, सहकारिता आदि में कार्यरत अधिकारियों को एक दो दो तीन पदों के उच्च प्रभाव देकरअर्बन पर प्रतिमाह की वसूली करने के लिए जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिये गये। ताकि एक तरफ उनका वेतन बचाया जा सके दूसरी तरफ उनको ब्लैकमेल कर भ्रष्टाचार की मोटी वसूली करने के साथ मनचाही लूट का तांडव नृत्य अनवरत चलाया जा सके।

18 सालों में इस घोर भ्रष्ट जालसाज शिवराज ने अपनी मोटी वसूली के लिए एक तरफ कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों का भविष्य बर्बाद किया। तो दूसरी तरफ 18 सालों में अधिकांश विभागों में स्वीकृत स्टाफ का केवल 25 से 40ञ स्टाफ ही रह गया परंतु भर्तीयां नहीं कर लगभग 15 लाख से ज्यादा उच्च शिक्षित इंजीनियर डॉक्टर टेक्नीशियन डिग्री धारी की जिंदगी बर्बाद की। परंतु विभागों में कार्य करवाने के लिए मुख्य रूप से शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक अध्यापक आदि से ठेके दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य करवा कर जिनकी संख्या लगभग 2 लाख है, स्वास्थ्य विभाग में लाखों आशा उषा कार्यकर्ताओं से लेकर नर्सों कंपाउंडर से डॉक्टर तक लाखों की भर्ती ठेके पर करके एक तरफ नियुक्ति में मोती वसूली तो दूसरी तरफ ठेके काम खत्म होने पर ठेके को नवीनीकरण के नाम पर मोटी वसूली से यौन शोषण तक का खुला तांडव चल रहा है।

ऊर्जा की सभी विद्युत कंपनियों में मुख्य रूप से विद्युत वितरण कंपनियों में कर्मचारियों का बिना प्रशिक्षण सुरक्षा उपकरण दिए 8 से 10000 में 12 12 घंटे काम लेकर चलती लाइनों के खंमों पर चढ़वा कर मौत का तांडव करवाया जा रहा है। मृत्यु हो जाने पर वहां बैठे कंपनियों के नियमित इंजीनियर साफ पल्ला झाड़ देते हैं। एसिड ठेका अस्थाई मिनट गर्मी को मृत्यु के बाद में उसके परिवार को भिखारी बनाकर छोड़ दिया जाता है। जबकि उनके नाम से कम्पनियों में रु. 30000 प्रति माह का वेतन निकाल रुपए से 10-20 हजार प्रति माह का वेतन वहां बैठे इंजीनियर भ्रष्ट आईएएस अधिकारी से मंत्री और मुख्यमंत्री तक बंट जाता है। के साथ हर विभाग में हजारों डिग्री धारी कंप्यूटर ऑपरेटरों जो 5 से 30 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं पांच आठ रु. 10000 में काम करवाया जा रहा है। पीछे भीइस डकैती शिवराज का ही लूट और वसूली का षड़यंत्र चल रहा है।

बेशक 18 साल में इतने किए हुए कर्मकांड का यह खोपड़ी का बाल भी नहीं यह जानकारी, परंतु यहां इस सिंगल हड्डी डकैत की पानी का उचित यह है कि जब इतना लूट चुके हो और अब जनता हुआ संघ व पार्टी के लोग नहीं चाहते। तू क्यों चुनाव लड़ने के पीछे पड़े हुए हो टिकट दिया नहीं गया है इसके विपरीत हर दिन सैकड़ो करोड़ के टीवी समाचार पत्र पत्रिकाओं, ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों, इंटरनेट साइट गूगल आदि पर फर्जी विज्ञापनों की नौटंकी की जाकर कर्ज लेकर जनधन की बर्बादी कर प्रदेश को कर्ज में डुबोया जा रहा है। स्वयं पीछे हटकर चुनाव लड़ने से मना कर साथ सम्मान भेजो हो लालच त्याग दो थोड़ी बहुत इज्जत बची रहेगी।

चंद्रमा पर यान पूर्णतः बकवास

पेज 1 का शेष

जबकि वहां पहुंचना संभव नहीं। मैं तत्काल अपने कंप्यूटर पर आर्मस्ट्रांग की चंद्रमा की लैंडिंग की फोटो डाउनलोड करके उनको बड़ा करना शुरू किया। तो देखा सब झूठ और बकवास है। यह सारा वातावरण पृथ्वी का ही था। क्योंकि दूर पीछे झाड़ झंकार और रेगिस्तान दिख रहा था। बस मैंने इस सिद्धांत को सामने रख पूरी कहानी लिखी और दुनिया के अनेकों टीवी चैनल जिसमें डिस्कवरी भी था। सीएनएन बीबीसी को भी भेजी। डिस्कवरी चैनल वाले उनके पीछे पड़ गए और मालूम पड़ा कि अमेरिका ने वह सारा षड्यंत्र मन्च लगाकर धरती पर ही पूरा किया था। सारे फर्जी फोटो जारी कर अपनी उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति का दबदबा बनाने के लिए चंद्रमा पर उतरने की झूठी कहानी पढ़ी थी।

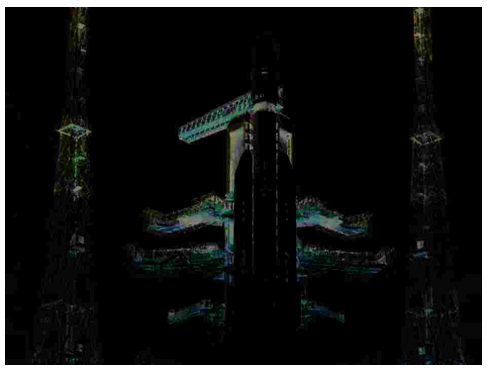

वह कहीं नहीं गए थे उन्होंने कैलिफोर्निया के मरुस्थल में वे सारा सेट लगाकर सारीकारस्तानी से फोटो खींचे गए थे। जिसकी पोल डिस्कवरी चैनल ने बरसों पहले टीवी परप्रसारित की थी। अमेरिका ऐसे कांड 1910 से बीमारियों को फैलाने की आड़ में औषधियोंकी भारी भरकम बिक्री, कृषि, चिकित्सा, अंतरिक्ष, रसायन, भौतिकी, युध्द, विधि, मधुमेह, बीपी, एड्स, हेपेटाईट्स, स्वाईन फ्लु, कोरोना आदि सभी क्षेत्रों में कर अपना दबदबा बना व्यवसाय बढ़ाने में करता रहा है। मैंने भीहवाई आज उड़ाया है। बहुत सारी किताबें हवाई जहाज उड़ान से संबंधित और हवाई जहाज की तकनीकी पर पढ़ी हैं। हवाई जहाज पृथ्वी के वातावरण में हवा पर अपनी पक्षियों कीभांति बनावट के कारण तैरता है। जिस में लगे पंखे या प्रपोलर, और जेट इंजन में वही प्रोपलर अंदर की तरफ होते हैं। जोकि पेट्रोल के इंजन से घूर्णन गति पैदा कर पंखोंको घुमाते हैं अंदर या बाहर। जो पृथ्वी के वातावरण में वायु को बाहर से अंदर खींचकर पीछे की तरफ फेंकते हैं। और वह पक्षी की तरह बना हुआ विमान डैनों के कारण तैरताहुआ रडर से नियंत्रित दिशा में आगे बढ़ता है। जमीन से उड़ान भरने और उतरने के लिए एलरान और दाएं बांये मुडने के लिए रडर काम करता है। जो कि पूंछ में होता है। बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि जब अंतरिक्ष में सब कुछ शून्य है। तो विमान काहे पर तैरेगा। किस ईंधन का उपयोग करेगा क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में पेट्रोल ऑक्सीजन केसाथ जलकर घूर्णन गति पैदा कर तैरता है। अंतरिक्ष में सब कुछ शून्य होने के कारण कोईभी ईंधन कार्य नहीं करेगा। अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। रसायन क्रियाशील नहीं होते। फिर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 32,80,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही वहां ना तो हवा है। ना किसी पिंड के त्वरण का गुरुत्वाकर्षण। बेशक अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाकर वहां पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वे वहां रॉकेट ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ देता है वे वहीं पर पड़े रहते हैं। और वहीं से अपनी उसी स्थिति में पढ़े रहकर रेडियो तरंगों का एंटीना के माध्यम से उपयोग कर हमारे मोबाइल सिस्टम दूरदर्शन इंटरनेट आदि को चलाने में सहायक रहते हैं पर वे भी पृथ्वी की कक्षा से 1000-2000 किलोमीटर ही ऊपर तक जा पाते हैं। वैसे अधिकांश मानव निर्मित उपग्रहों की यह दूरी पृथ्वी से लंबवत 500 से 2000 किमी तक ही होती है। परंतु चंद्रमा से पृथ्वीकी दूरी 32 लाख 80 हजार किलोमीटर है कितना भी कश लगा लिया जाए कोई भी रॉकेट 10 20000 से ज्यादा अधिकतम 1लाख किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष में नहीं बढ़ सकता। यह सारी कहानियां पूरे विश्व के अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, रूस और भारत की केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग कर, वहां की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्ट सरकारों का अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने उस पर अपनी उपलब्धियों का मानसिक दबाव बनाने की है। जो केवल बकवास और झूठ का पुलिंदा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग और जनता को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र है। जो आज नहीं तो कल इस पाखंड का भी खुलासा होगा ही होगा। धरती पर देश की जनता और बच्चे भूख से बेहाल हैं। 50 करोड़ बेरोजगार हैं। उन धूर्त राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों को उसकी चिंता कदापि नहीं उन्हें अपनी मौज मस्ती और प्रयोगशालाओं में उपलब्धि दिखाने में कोई कहीं चांद पर भी नहीं पहुंचा ना पहुंच सकते हैं। कोरी गप्प है। आर्मी स्ट्रांग को कैलिफोर्निया के मरुस्थल में उतारकर सारा शूट किया गया था।

अमेरिका यह भ्रम पिछले 54 सालों से केवल दुनिया को झूठी शक्ति प्रदर्शन का दुष्प्रचार है।

हवाई जहाज पृथ्वी के वायुमंडल में पेट्रोल को जलाकर हवा पर पृथ्वी की त्वरण शक्ति के विपरीत अपनी हवा पर तैरने योग्य बनावट के कारण तैरता है। जब अंतरिक्ष में सब कुछ 0 शून्य हैं। लाखों किलोमीटर की दूरी में किसी भी पिंड की कोई त्वरण शक्ति नहीं कोई माध्यम नहीं तो किस दिशा दशा मैं चलेगा और कैसे किसी यान को गति, दिशा मिलेगी।

मेरे पास भी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस था मैंने भी कॉकपिट में बैठकर 8 घंटे की कुछ देर के लिये कंट्रोल बार थाम कर उड़ान भरी है। जो उड़ान के सिद्धांत पूर्वजों ने लिखी पुस्तकों के आधार पर ही मैं यह साझा कर रहा हूं जहां तक अमेरिका का सवाल है तो ऐसे अपनी मोटी कमाई करने की सैकड़ों, दुनिया पर अपने शक्ति प्रदर्शन डर भय पैदा करने सन 1900 से अमेरिका छोड़ा करता है कुछ सच हो जाती हैं और कुछ हवा में ही रहती हैं। विटामिंस मिनरल्स प्रोटींस केवल अपना और रासायनिक माल जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है बेचने का षड्यंत्र पिछले 100 सालों से चल रहा है उससे लाखों करोड़ों की कमाई हर वर्ष अमेरिकी कंपनियां करती हैं जबकि आज तक कोई ठोस प्रोटीन विटामिन मिनरल्स का तक नहीं है उसके पास। ऐड्स क 40 साल के बाद में भी वायरस नहीं मिला। पर उसका भाई पैदा कर अब अरबों रुपए प्रति दिन के कंडोम जरूर पूरी दुनिया में बैचता है।

हेपेटाइटिस 1990 के दशक में हजारों करोड़ के टीके पूरी दुनिया में बेचकर मोटी कमाई की गई वही हाल स्वाइन फ्लू करोना कारी हुआ वह भी लाखों का उत्पत्ति के बेचकर मोटी कमाई की गई उल्टा ही उस टीके से करोड़ों लोगों को अकाल मौत हुई। माइक्रोसॉफ्ट के ब्रिगेड के बनाए हुए मॉडर्ना के टीके से 7000 अमेरिकी मरीन कॉर्प्स 72 घंटे में अकाल मौत का शिकार हुए जिसके कारण 27 जुलाई 2021 को बिलगेट को पकड़कर 1 अक्टूबर को फांसी पर लटका दिया गया यह खबर आज तक बाहर क्यों नहीं आ रही जबकि यह खबर realrawnews.com अमेरिका की साइट पर चल रही है। जिसे खोजा जा सकता है। तबसे बिल गेट कहां गायब है? गाहे-बगाहे उसके पुराने फोटो भास्कर जैसे पेपर भी टीके की इज्जत बचाए रखने के छापते रहते हैं।

चंद्रमा मंगल पर पानी की कहानी जो वर्षों तक चलाई जाती रही। उसको ही मैंने खंड खंड बिखेर दिया था। जिस पिंड पर बादल वहां तरलता जहां तरलता वहां जीवन जहां तरलता वहां बादल बनेंगे वहां बादल बनेंगे तो वहां तरलता होगी जिसे देखने के लिए आपको चंद्रमा पर मंगल पर नहीं जाना है। वह यहां दूरबीन से भी दिख जाएंगे जैसे कि शुक्र और शनि पर दिखते हैं।

यश सिद्धांत सन 2006 में अचानक मस्तिष्क में उठे विचारों के तूफानों को अंत में संग्रहित कर जोड़ा गया और छापने के बाद, चंद्रमा और मंगल का पानी सूख गया। अब यह अमेरिकी भड़वे वह गप्प नहीं सुनाते।

26 दिसंबर 2004 को मलाया सुमात्रा जावा द्वीपों पर सुनामी अमेरिकी बम विस्फोटों का परिणाम था। 27 दिसंबर 2004 की रात 12:30 बजे पूरे यूरोप और एशिया के समाचार पत्रों को तथ्यों के साथ ई-मेल पर चिपका देने से 28 नवंबर 2004 से अमेरिका ने पूरी दुनिया में प्रभावित देशों में बांटकर सबको शांत करने की कोशिश की थी? दूसरी तरफ भारत की वैमानिकी निर्माण विकास और रखरखाव की तैयारी को समझा जाए तो जिस रूस ने 1935 40 में बनाया मिग-21, जिससे रूस ने जर्मनीसे द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। बाद में 1956 में उसे लगभग 3000 से ज्यादा मिग-21 को उसने अपने स्क्रैप यार्ड में खड़ा कर दिया था जिसे भारत में 1959 में 1000 जहाजों का बेड़ा खरीदा मिग-21 को 2020 तक ना तो वहअपनी वायु सेना से हटा पाया ना ही ढंग से उनका रखरखाव और न ही पुनुरोत्पादन कर पाया। यहां तक की सभी वायु सेना के मिग 21, 23, 27, 29 से लेकर सुखोई 30 सी हेरियर, मिराज 2000, हाल ही में खरीदा गया राफेल जो फ्रांस सन 1985 में बनाया था, उस 30 साल पुराने कबाड़ को भी भारत में जिसकी कीमत 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा नहीं थी लालची भेडियों ने 1650 करोड़ से $1731 करोड़ तक में खरीदा।

जिस देश के वैज्ञानिकों में इतनी भी समझ ना हो, कि भाई विदेशों से खरीदे हुए युद्धक विमानों की श्रृंखला को भारत में तैयार कर पाती। जबकि फ्रांस इजरायल रूस अमेरिका जैसे देशों को भारत से लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। मिट्टी के भाव खरीदा बाबा हेलो अयस्क हमारे यहां सोने से ज्यादा महंगी कीमत में हथियारों के रूप में लौटकर आता है। जब हम खुद के यात्री, युद्धक, परिवहन विमान तो बना नहीं पाए 75 साल की आजादी के बाद में भी हम छोटे छोटे से देशों से जहां की आबादी केवल चार महानगरों की आबादी से भी कम है वहां से खरीदते हैं तो हम अपनी वैमानिकी और अंतरिक्ष उड़ान पर कैसे इठला सकते हैं।जाहिल, वाचाल जिन्हें देश की संपत्तियों को बेचकर खाने विदेशों में बहुत मस्ती करने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच कर देश को बर्बाद करने की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना जातिवाद धर्म बाद के आधार पर जनता को लड़वाना। जिनकी खुद की कोई उपलब्धियां नहीं। जिनके मस्तिष्क में केवल षड्यंत्र भारत हो यह जनता को मूर्ख बनाने के लिए चंद्रमा पर पहुंचने का षड्यंत्र करते हैं।

'प्रकाश की गति' की भारतीय शास्त्रीय गणना

सनातन संस्कृति के महर्षि सायण 'प्रकाश की गति' की गणना

बचपन से ही हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि 'प्रकाश की गति' की खोज डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टेंसेन रोमर ने की थी।

साथ ही कहा जाता है कि रोमर से पहले गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों बहुत प्रयास के बाद भी 'प्रकाश के वेग' को नहीं जान पाए थे। हालांकि, गैलीलियो इतना तो समझ गए थे कि ब्रह्मांड में 'प्रकाश की गति' सबसे तेज है, लेकिन वह यह कभी नहीं जान पाए कि वास्तव में 'प्रकाश की गति' है कितनी... अंततः... रोमर ने पहली बार 1676 में प्रकाश का वेग निर्धारित किया था। जबकि, वास्तविकता काफी चौंकाने वाली है। क्योंकि, सनातन... संस्कृति के महर्षि सायण, जो वेदों के महान भाष्यकार थे, ने 14वीं सदी में ही 'प्रकाश की गति' की गणना कर डाली थी... जिसका आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का चौथा श्लोक था, जिसमें लिखा है -

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमा भासि रोचनम्।

(ऋग्वेद 1.50.4)

अर्थातृ हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सर्वसुन्दर तथा प्रकाश के दाता और जगत् को प्रकाशित करने वाले हो।

उपरोक्त श्लोक पर टिप्पणी करते हुए महर्षि सायण ने निम्न श्लोक प्रस्तुत किया था -

तथा च स्मर्यते योजनानां सहस्त्रं द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोऽस्तुते।

(सायण ऋग्वेद भाष्य 1.50.4)

अर्थातृ आधे निमेष में 2202 योजन का मार्गक्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार है।

इस उपरोक्त श्लोक से हमें प्रकाश के आधे निमिष में 2202 योजन चलने का पता चलता है।

अब हम समय की ईकाई क्षनिमिष तथा दूरी की ईकाई क्ष्योजन को आधुनिक वर्तमान इकाईयों में परिवर्तित कर सकते है।

किन्तु, उससे पूर्व हम प्राचीन समय तथा दूरी की इन इकाईयों के मान को जान लेते हैं। इस बारे में हमारी मनुस्मृति कहती है -

निमेषे दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कलाः।
त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यात् अहोरात्रं तु तावतः।
(मनुस्मृति 1-64)

इस के अनुसार पलक झपकने के समय को 1 निमिष कहा जाता है!

18 निमीष = 1 काष्ठ;
30 काष्ठ = 1 कला;
30 कला = 1 मुहूर्त;
30 मुहूर्त = 1 दिवस (लगभग 24 घंटे)

अतः एक दिवस (24 घंटे) में निमिष हुए :-

24 घंटे = 30X30X30X18= 4,86,000 निमिष

जबकि, आधुनिक गिनती की इकाई के हिसाब से 24 घंटे में सेकेंड हुए:-

24X60X60 = 86,400 सेकंड

अतार्थ 86,400 सेकंड =4,86,000 निमिष

अतः 1 सेकंड में निमिष हुए :

1 निमिष = 86400 /486000 = 0.17778 सेकंड

अंततः 1/2 निमिष = 0.17778/2 = 0.08889 सेकंड

इसी तरह अगर हम योजन की बात करें तो श्रीमद्भागवतम 3.30.24, 5.1.33, 5.20.43 आदि के अनुसार :-

1 योजन = 8 मील लगभग

तो, 2202 योजन = 8 X 2202 = 17,616 मील

अब हम अपने ऋग्वेद में उल्लेखित प्रकाश की गति' को यदि आधुनिक गणना पद्धति में बिठाते हैं तो हम पाते हैं कि....

सूर्य का प्रकाश 1/2 (आधे) निमिष में 2202 योजन चलता है अर्थात, 0.08889 सेकंड में 17,616 मील चलता है।

अर्थात, 0.08889 सेकंड में 'प्रकाश की गति' = 17,616 मील तो, 1 सेकेंड में = 17,616 / 0.08889 = 1,98,177 मील यानी 3,18,934.966 किलोमीटर

आश्चर्य है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी 'प्रकाश की गति' को 1,86,000 मील यानी कि 3,18,934.966 किलोमीटर प्रति सेकंड ही बताती है। कहने का मतलब है कि खगोल विज्ञान के जिस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान ने 1676 में खोजा और बताया... वह ज्ञान तो हमारे ऋग्वेद में हजारों वर्षों पूर्व ही ऋषियों ने उल्लेखित किया है। इसका मतलब हुआ कि जिस समय यह पश्चिमी सभ्यता के लोग जंगलों में नंग धड़ंग रहते थे.... और, चूहे बिल्ली आदि मार कर खाया करते थे... उस समय हमारे विद्वान ऋषि-मुनि खगोलशास्त्र और विज्ञान में अंतरिक्ष की गहराइयाँ एवं प्रकाश की गति नाप रहे थे...!

क्योंकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद को निर्विवाद रूप से मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। हमारी ऐसे वैदिक विज्ञान के कारण हमें अपने धर्मग्रंथों तथा अपने सनातन धर्म पर आखिर क्यों गर्व नहीं होना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

WHO स्वास्थ्य के नाम डराओ लूटो

(पेज 1 का शेष)

विश्व गुरू बनने के सपनों को ध्वस्त कर नशे में डुबो अनेकों बीमारियां फैला हिंदुओं को नष्ट करने का षड़यंत्र क्रिश्चियन व मुस्लिमों के अंतरर्राष्ट्रीय संगठन भी कर रहे हैं। उसमें चांडाल मोदी मोटा कमीशन हड़प कर सबको खुली छूट दे रहा है। पिछले 9 साल के इतिहास को उठाकर देखें तो सब स्पष्ट हो जायेगा।

डब्ल्यूएचओ और सरकार की जालसाजियों के बारे में पहले दिन 23 मार्च 20 से ही में सूचित कर रहा था।

मेरा सारा सच बाद में स्वयं डब्ल्यूएचओ के साथ पूरी दुनिया की सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय एवं डाक्टरों ने भी स्वीकार किया।

बाद में टीका लगाने के लिए भी मैंने मना किया। पर लोग नहीं माने और मेरी सच्चाइयों पर जब तक सर्वोच्च न्यायालय के मोहर नहीं लगी। मैं मजाक का पात्र बना रहा।

अंडभक्तों जालसाजी पूर्ण कोविड के टीकों का पहला डोज, फिर दूसरा, फिर भी बच गए तो फिर तीसरा बूस्टर भी, जनता के पैसे से जबरदस्ती अकाल मौत का सामान शरीर में ठोक कर भी, हजारों करोड़ के मुफ्त के टीके लगाने का विज्ञापन पर भी जन धन खर्च किया गया।

टीके के सर्टिफिकेट पर भी उस राक्षस का भीफोटो उनकी जालसाजियों से जनता को जानबूझकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दवाइयों का उपयोग करने अकाल मौत देने का असर, 2 साल तक घातक पूरी तरह और उसके बाद भी जीवन पर्यंत रहने वाला है।

उसके परिणाम स्वरूप शरीर के कमजोर होने के कारण बार बार सर्दी खांसी जुकाम बुखार, शरीर के सारे जोड़ों का ढीला होना, जिसमें खासतौर से कंधे पुट्ठे और घुटनों का दर्द, अचानक हृदय व मस्तिष्क आघात से मृत्यु भी लगातार हो ही रही है। जो हर टीके लगवाने के साथ कभी भी संभव है। पर डरे नहीं परेशानी होने पर होम्योपैथी और आयुर्वेद में उसके असर को खत्म करने व उत्पन्न रोगों के समन करने की औषधियां हैं।

विश्व घातक स्वास्थ संगठन यथार्थ में अमेरिका और यूरोप की दवा, इंजेक्शन, विटामिन प्रोटीन और चिकित्सीय मशीन उत्पादक कंपनियों का षड्यंत्र कारी व्यवसाय संवर्धन संगठन है। जो पिछली एक शताब्दी से पूरी दुनिया में हर 10 साल में पहले कोई नई बीमारी फैलता है और उसकी आड़ में लाखों करोड़ की अपनी दवाइयां उपकरण सामग्री टीके बैचकर मोटी कमाई करता है।

पिछले 40 सालों का इतिहास देखा जाए, तो 1980-90के दशक में उसने एड्स की बीमारी फेंकी। उसकी आड़ में उसने जांच किट, और तब से अभी तक लाखों करोड़ के कंडोम पूरे देश और दुनिया में बैचकर, भारत में परिवार और समाज की नैतिकता को खंड खंड बिखेर दिया।

जबकि 40 साल गुजर जाने के बाद में भी आज तक ऐप्स करना तो कोई वायरस मिला न इलाज, क्योंकि ना कोई बीमारी थी और ना कोई इलाज। पर भयावह डर की कहानी ऐसी थी कि दुनिया के लोगों संभोग करने से पहले हमें कंडोम खरीद कर मोटी कमाई दो। फिर हेपेटाइटिस का डर भरा। उसकी आड़ में भी लोगों को कमजोर करने नपुंसक बनाने अरबों रुपए का टीका बेचा गया। 1988-89 से लेकर 93-94 तक और उसकी जांच की नई कहानी शुरू करके बीमारों को हर अस्पताल में लूटना शुरू कर दिया गया। फिर 2000 के आसपास शुरू किया गया। फिर उस चांडाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू कब ऐसा लाया पूरी दुनिया में वहां की सरकारों को खरीद कर वहां बैठे स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्णता एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और दवाइयों पर देश की जनता की चिकित्सा करके मोटी कमाई करते हैं और उन कंपनियों की करवाते हैं। ने अपनी फिर सलाह जारी कर दी और जानबूझकर मां की सरकारों को यात्रियों को उड़ानों को रोकने की नौटंकी शुरू कर आने जाने वाले यात्रियों की जांच के नाम पर फिर लूट मचाकर तांडव किया गया और जैसे ही उन हरामखोर चांडाल अमेरिकी कंपनियों का टीका पूरी देश दुनिया में बिकने लगा तो फिर बीमारी खत्म हो गई सन 2010 के दशक में फिर चिकनगुनिया आया या जानबूझकर अपने पैकेज्ड फूड मैं कीटनाशक और घातक प्रेजर्वेटिव मिलाकर अपनी मॉल चैन से बीमारी के रसायन खिलाकर जानबूझकर पहले बीमार बनाओ फिर अपना औषधियों मशीनों जांच किटों टीकों का हजारों गुना कीमत में माल बेंचो। और उसका 20-25% वहां की सरकारों, चिकित्सा मंत्रालयों मैं बैठे मंत्री, डॉक्टरों अधिकारियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद के पदाधिकारियों को, चिकित्सा संस्थानों को, निजी व सरकारी अस्पतालों को डॉक्टरों को, क्षेत्रीय मीडिया को खरीद कर चारों तरफ भय का वातावरण निर्मित कर, पहले करोड़ों की चिकित्सा के नाम पर हत्याओं और मौत का तांडव करवाओ।

जबकि कोई बीमारी हो ना हो। पर उसकी आड़ में अपना मोटा लाखों-करोड़ों की जांच किट, दवाइयां चिकित्सा उपकरण और अंत में टीके को बेंचो। जैसा कि अभी करोना में हुआ और हो रहा है। अब चुंकि मोबाइल और इंटरनेट अस्तित्व में आ चुका है।

फिर विश्व की भर्ती औद्योगिक ताकत के रूप में चीन ने भी मोटा कमीशन बांट इस विश्व घातक संगठन से हाथ मिला लिया। और पूरी दुनिया में सस्ता स्तर हीन घातक माल सप्लाई करने के लिए कुख्यात लाखों करोड़ के मास्क थर्मो गन, ऑक्सीमीटर, आर्किड बैच डालें। संजय अमेरिका इस पाखंड को पुख्ता करने के लिए चीन से वायरस फैलाने के सुरेंद्र की बात करता रहा एक दूसरे से दिखावटी नूरा कुश्ती करते हुए दोनों देशों की कंपनियां हजारों करोड़ कोरोना के नाम कमाती रही।

फिर बदलते समय के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसमें वॉलमार्ट अमेजॉन भारत की अंबानी अडानी टाटा बिरला आईटीसी युनिलीवर के साथ बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल भी अपनी कमाई में से 20 से 25% इस पाखंड को फैलाने और अपने मालवी को आने के षड्यंत्र में शामिल हो गए। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण गंदी बात हुई कि हमारे देश का भूखा भेड़िया जाहिल मोदी, इस करुणा की तैयारी को में सन 2016 से लगा हुआ था अरबों रुपए की कोरोना की किट की आपूर्ति पूरे देश में कर दी गई थी और तैयारी चल रही थी उसके पहले उसने जानबूझकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर उस हरामखोर अनपढ़ गवार ने देश में कैशलेस की नौटंकी की जब वह सफल नहीं हुई तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की ताकि देश के सारे नकदी लेन-दन पर चलने वाले छोटे व्यवसाय, उद्योगों को खत्म कर दिया जाए। सारे व्यवसाय को ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया जाए।

ताकि उनके लाभ में से मोटा लाभ चुनकर आए भूखेरे श्वानों, यथा विधायक सांसद मंत्रियों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री व परीक्षा से चुने भारतीय प्रताड़ना सेवा के मोटी चमड़ी के सूकरो को करोड़ों में महीना मिलता रहे। इसलिए वह सब आंख मीच कर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम बनकर आदेशों का पालन कर देश में करोना के नाम पर 24 घंटे टीवी मोबाइल समाचार पत्रों में दहशत बांट और मुंह पर मास्क बांधने के लिए विवश कर जानबूझकर बीमार बना कर करोड़ों लोगों का नरसंहार करवाने के साथ, अब टीके का पाखंड कर रहे हैं और सौ करोड़ टीके लगा कर अपनी उपलब्धि को महानता का कृत्य बता रहे हैं। जबकि गिट्टी को को बनने में 15-20 साल लगते हैं। वाटिका नवंबर दिसंबर 2020 में ही बना लिया गया था।

टीका लगने के बाद उसी स्वास्थ विभाग के जो यह पाखंड कर रहा है। 20,000 से ज्यादा डॉक्टर की मौत हो चुकी है। करोड़ों लोग जिसमें हजारों छोटे-मोटे नेता, अधिकारी, हजार से ज्यादा पत्रकार, टीका लगने के बाद मौत के शिकार हो चुके हैं। पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिले धन और 5उ मोबाइल सेवा जिसके माध्यम से 5उ मोबाइल उपयोग करने वाले और टीका लगाने वाले उपयोगकर्ता के दोनों एक दूसरे से शारीरिक मानसिक रूप से जुड़ जाएंगे। उनकी हर गतिविधि पर, मस्तिष्क की तरंगों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां नजर रखकर अपना माल बेंचने का षड्यंत्र पूरा कर रही हैं। इसके लिए 125 अरब डॉलर विश्व बैंक ने दो किस्तों में मोदी को दिए थे।

देश और दुनिया में अमेरिका और चीन की कंपनियों ने पिछले 42महीने से चलाया जा रहा करोना के पाखंड में और भी बहुत सारे बड़े-बड़े कांड किए। महामारी की आड़ में जबकि कोई भी व्यक्ति बीमार किसी भी देश में सड़कों पर बाजारों में दुकानों में कार्यालयों फैक्ट्रियों खेतों उद्योगों में नहीं मरा। सब को भयभीत कर मानसिक संत्रास से लिखकर बीमार बनाया और ले जाकर अस्पतालों में उनकी वहां के बोर्ड बाय ओनर सोनी जिसको जो मन में आया इंजेक्शन और दवाई लगाकर हत्या कर दी गई।

उसके आधार पर जो तालाबंदी का नाटक किया गया उसका सारा फायदा अमेरिका की वॉलमार्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट को मिलने के साथ है चीन के उद्योगों को फायदा हुआ और भारत में भी वॉलमार्ट अमेजॉन के साथ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, आईटीसी युनिलीवर आदि के शॉपिंग मॉल से भी लाखों करोड़ का इन्हीं का माल बिका। इनकी संपत्तियां चौगुनी से 10 गुनी हो गई। बदले में देश के 30 करोड़ लोग बेरोजगार होने के साथ लगभग एक करोड़ छोटी दुकानें उद्योग फैक्ट्रियां स्थाई खर्चों के चक्कर में नष्ट हो गए।

गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मोबाइल कंपनियां सभी उपयोगकर्ताओं का हर तरह से करती घोर शोषण

(पेज 12 का शेष)

वरन इसके विपरीत मोदी के कड़वे सच को वीडियो में लोड करने पर या संदेशों में भेजने पर उसको यह जालसाजों का गिरोह उड़ा देता है। अभी भी अनेकों वीडियो इसने फेसबुक टवीटर, गूगल, युटयुब, vimeo, vidyard, dailymotion, metacafe, से उड़ा दिए। क्योंकि उसके बदले में यह मोटी वसूली हजारों डॉलर में कर लेता है। यह वही सूअर है। जिसने आई एस आई के लिए अपनी फेसबुक के माध्यम से हमारे देश में और पूरी दुनिया में मुस्लिम लड़ाकों की भर्ती करवाने में सहयोग दिया था। यही कारण है इनको चीन और रूस में चलने नहीं दिया गया। भारत में भी मैं पिछले 23 साल से इंटरनेट के सारे इस प्रकार के एप्स को अनेकों कंपनियों से विकसित करने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि यह सारा खेल भारत के साथ अमेरिका से संचालित किया जाता है। हमारे 130 करोड़ भारतीयों का सारा डाटा सारी वीडियो सारी जानकारियां अमेरिका में एकत्रित की जा कर उनका भारी व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाता है। इसको जनता समझे। अभी भी फेसबुक टवीटर, गूगल, युटयुब, vimeo, vidyard, dailymotion,metacafe, Billgate of microsoft का उपयोग करना मेरे लिए इसलिए मजबूरी बन गया क्योंकि यूट्यूब ने हीं मेरे वीडियो को 15 जून से ब्लॉक कर दिया था। वीडियो को होस्ट करने के लिए दूसरी साइट फेसबुक ट्विटर ही भारत में सुलभता से उपलब्ध है। इसलिए इस हरामखोर की फेसबुक का मुझे पुनः उपयोग करना पड़ा। पर यहां पर भी यह वीडियो इंबेड कर के अपनी साइट लिंक करने पर भी यह मेरी साइट का ही दुरुपयोग कर लेता है। और तभी वीडियो देखने देता है जिसका फेसबुक पेज होता है। हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए जो कंप्यूटर साइंस वेब टेक्नोलॉजी पर काम करती है।

अपने भारत में ही इसके लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग कर भारत के लोगों को ऐसा वृहत खुला विचार विनिमय का मंच उपलब्ध करवाएं। ताकि भारत में इस फेसबुक टवीटर, गूगल, युटयुब, vimeo, vidyard, dailymotion,metacafe, Billgate of microsoft का सदा के लिए बहिष्कार किया जा सके। जहां से यह सूअर सबसे ज्यादा हजारों करोड़ डॉलर की प्रतिमाह कमाई करता है। भारतीय, दुनिया के सभी देशों के पाठक गण इस विषय की गंभीरता को समझ इस पर कार्य करना शुरू करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने और खास तौर से सोशल साइट्स व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम सिग्नल ट्विटर व अन्य इन जैसी अनेकों साइटों ने पहले जनता को मुफ्त की सेवाएं दी पर मुफ्त की सेवाओं की आड़ में उसका डाटा बातचीत एकत्रित कर खुले में नीलाम किया जा रहा है। और यह कहना कि वह एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। सब बकवास है। सब का डाटा अनेकों तरह से जिसमें आदतें खर्च खरीद बिक्री जीवन स्तर मित्रों की संख्या, उनकी आदतें, मित्रों का स्तर आदि अनेकों तरह का सदुपयोग किया जा रहा है। कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं दी जा रही।

दूसरी तरफ अभी जो षड्यंत्र किया गया। वह 99.99% लोगों को समझ में ही नहीं आया। पिछले 2 महीने से व्हाट्सएप व अन्य साइट आपके द्वारा भेजे वीडियो को धीरे-धीरे कंप्रेस करके छोटे से छोटा बना देती थी।उससे जनता उपभोक्ता या मोबाइल धारी का का न केवल डाटा कम खर्च होता था वरन आपके मोबाइल की स्पेस भी कम भरती थी । पिछले एक-दो महीने से अब वह वीडियो कंप्रेस होकर कम नहीं होता है। एचडी के नाम पर आपको जितने डाटा का वीडियो होता है वह उतना का उतना ही डाटा का वीडियो हर मोबाइल मेंअपनी यात्रा करके अपना स्पेस घेर के मोबाइल को जाम करने के साथ-साथ आपका डाटा भी उसी गति से खर्च करके वसूली करता है। आपके मोबाइल की जासूसी न केवल गूगल माइक्रोसॉफ्ट चीन आदि की अनु को कंपनियां करने के साथ-साथ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी स्कूल कॉलेज व अन्य प्रकार कीसभी जानकारियां बैंक खाता भुगतान की क्षमता तरीके आदतें सबका अध्ययन केवल निजी क्षेत्र में बल्कि सरकारी क्षेत्र में भविष्य की हार जीत बातचीत मित्रों की संख्या आदि सबका विश्लेषण करने के लिए सैकड़ों कंपनियां भारत में कम कर रही हैं और एआई भी अब भारी षड़यंत्रकारी कार्यों को अंजाम दे रहा है।

जहां तक देश के जाहिल प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है। तो उसे बूढ़े लालची गिद्ध को जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी चीन अमेरिका पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र भी सड़ा गला मांस रुपया कमिशन ड्रग्स यात्रायें सम्मान भी देगा। उसको वह पूरा देश देश की जनता व उसके प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन बेंचने, गिरवी करने देश की सीमाओं में कॉलोनी काटने जासूसी षड्यंत्र करनेदेश की जनता संसाधनों सी को कमजोर करने अपने सम्मान और कमीशन की कीमत पर अमेरिका फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इजराइल से कबाड़ा खरीदने आदि सारे षड्यंत्र करेगा।

जल के सत्ता में आने के बाद देश की जनता को हर तरीके से लूटने निचोड़ने बर्बाद करने उसका डाटा विदेशी कंपनियों को सौंपने का हर षड्यंत्र किया गया।जिसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर ही यहां की कंपनियां है करो नहीं लगभग 2 करोड़ से ज्यादा खातों में न केवल डकैतियां डाली ऋण बांटे और कई गुना लूटने के बाद में भी उन्हें परेशान करने के साथ दोस्तों में भी बदनाम किया इसके साथ ही खुले में क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन गेम जुआ सट्टा क्रिकेट का सट्टा करने करवाने वालों के लिए भी वह डाटा उपलब्ध करवाया गया। यह सब कुछ वैध करने के बारे में भी स्वयं मोदी उसकी तरफदारी करता है। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन जुये सट्टा क्रिप्टोकरंसी को वैधानिक बनाने का भी पिछले तीन-चार सालों से लगातार प्रयास करके जनता को लूटने के साथ जनता के साथ देश का भविष्य व अर्थव्यवस्था बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसके लिए आधार कार्ड को पैन नंबर बैंक खाता ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल की फीस राशन गैस, व्यवसाय आयकर जीएसटी व अन्य सभी करों, सरकारी कार्यों में अनिवार्य कर सबको मकर जाल में उलझने बर्बाद करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। इसीलिए अब मोबाइल कंपनियां भी बड़ी -बड़ी फाइलें बनाकर उत्तरोत्तर डाटा जो वीडियो जेपीजी पीडीएफ फाइलों को संपीड़ित कर कम करने की अपेक्षा उनको यथावत रख ज्यादा वसूली करने, मोबाइल जामकर खराब करने नए मोबाइल खरीदने का षड्यंत्र भी कर रही है। जनता इसको समझे।

विकास के लिए हरियाली की बलि इंदौर में घट गए 10 प्रतिशत जंगल

(समय माया)

टू-टियर सिटी में शामिल इंदौर में विकास कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। तीन साल के भीतर कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। इसमें मेट्रो से लेकर इंदौर-खंडवा राजमार्ग और इंदौर-सनावद ब्राडगेज सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट को आकार देने के लिए जिले में जगह-जगह वनभूमि को अधिग्रहित किया गया है। इस कारण इंदौर वनमंडल में दस प्रतिशत वनक्षेत्र घट गया है।

इंदौर वनमंडल में इंदौर-महू, चोरल और मानपुर का 11 हजार हेक्टेयर का वनक्षेत्र है। विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू होने से एक हजार हेक्टेयर वनभूमि कम हो चुकी है। जंगल का दायरा घटने से हरियाली कम हुई है। इसके पीछे दूसरी वजह अवैध कटाई भी है। वैसे इन दिनों नई अनाज मंडी के लिए माचल वन क्षेत्र में वन भूमि देने को लेकर सर्वे का काम चल रहा है।

---

195 हेक्टेयर जंगल से गुजरेगी रेलवे

महू-सनावद के बीच बड़ी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए रेलवे और वन विभाग ने सर्वे किया। उसमें 215 हेक्टेयर वनभूमि चिन्हित की गई। इसमें इंदौर वनमंडल की 195 और बड़वाह वनमंडल की 30 हेक्टेयर भूमि में मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए करीब चालीस हजार पेड़ काटे गए हैं। बदले में विभाग को झाबुआ में जमीन मिली है। साथ ही पौधारोपण के लिए भी रेलवे से राशि मिलने का इंतजार हो रहा है।

रात में कर रहे सुरंग का काम

इंदौर-खंडवा और एदलाबाद राजमार्ग का काम डेढ़ साल पहले शुरू हुआ है। राजमार्ग के लिए इंदौर वनमंडल से 80 हेक्टेयर वनभूमि अधिग्रहित की गई है। सिमरोल-चोरल के बीच दो स्थान पर सुरंग होगी। 800 मीटर की दोनों सुरंग के लिए जंगल की जमीन पर काम चल रहा है। वन विभाग ने इसके लिए रात में काम करने की मंजूरी दी है, जबकि एजेंसी सड़क निर्माण भी कर रही है।

परिवहन क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए इंदौर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मेट्रो के लिए वन विभाग ने भी कुछ जमीन दी है। गांधीनगर में मेट्रो स्टेशन और डिपो के लिए वन भूमि अधिग्रहित की गई है। करीब 35-40 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी बिजासन रमणा वनक्षेत्र की जमीन दी है, मगर एयरपोर्ट की तरफ से काम शुरू होना बाकी है। वहीं चोरल रेंज में आने वाले बेका गांव में सिंचाई विभाग ने तालाब बनाने के लिए वनभूमि ली है। तालाब बनने से आसपास के 15 गांवों में पानी की पूर्ति हो सकेगी। तालाब का काम पांच महीने पहले शुरू हो चुका है। करीब 40 हेक्टेयर वन भूमि ली गई है।

मोरोद माचल में नई मंडी

मोरोद माचल में नई अनाज मंडी बनाई जाएगी। इसके लिए डेढ़ साल से शासन सर्वे करने में लगा है। करीब 200 हेक्टेयर जमीन पर मंडी आकार लेगी। इसके लिए छह महीने पहले मंत्री और अधिकारियों ने भी दौरा किया था। वैसे अभी वन विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

तीन साल में एक हजार हेक्टेयर वनभूमि अधिगृहित

स्मार्ट इंडस्ट्रीज पार्क भी रेलवे और राजमार्ग के बाद अब स्मार्ट इंडस्ट्रीज पार्क की परियोजना बनाई जा रही है। काम अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। पार्क के लिए एकेवीएन 300 हेक्टेयर वनभूमि लेगी, जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे। ये पार्क बेटमा में बनने जा रहा है। सर्वे का काम कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है।

'रेवड़ी कल्चर' पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र और राजस्थान सरकार से मांगा जवाब- कहा

वोटरों को लुभाने करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग हो रहा

(समय माया)

विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार पर मुफ्त रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाया है। इसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल, राज्य सरकारों की ओर से की जा रही घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को भेजा गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से यह मामला लंबित है। इस मामले में अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। यह याचिका कई साल से लंबित है, उस पर अभी विचार ही हो रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका कहा- सरकारें 5 साल काम नहीं करती, आखिरी में देती हैं लालचः जनहित याचिका में क्या कहा कि राज्य सरकारें चुनाव के पहले कई लोकलुभावन योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है। सरकारें पांच साल काम नहीं करती है, आखिरी में जनता के टैक्स का पैसा लुटाकर वोट बटोरने का प्रयास करती हैं। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र पर नजर रखी जानी चाहिए, साथ ही राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए कि घोषणा पत्र के बड़े-बड़े दावों को कैसे पूरा करेंगे।

चार हफ्ते में देना होगा जवाबः अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को इस तरह की घोषणाओं पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इसमें पूछा गया है कि आप जो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं उसे पूरा कैसे करेंगे।

जो लूट सके लूट अंत काल पछतायेगा प्राण जायेंगे छूट

पेज 12 का शेष

इसको तो 36 लोगों की अकाल मौतें जो कुएं में डूबने से हुई थी जहां 60 से 70 आदमी मरे थे तत्काल अपने नाकामियों अपराधों को छुपाने, उसको कुयें भराई करवा कर सारे सबूत सदा के लिए मिटा दिये गये।

आदिम जाति, आबकारी, परिवहन, पंजीयन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, खनन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राजस्व, कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास पंचायत शहरी विकास बिहार विभाग में व अन्य हर शासकीय विभाग का जो महीना मिल रहा है और अपने आका शिवराज के चरणों में डालकर इंदौर मैं भू, कॉलोनी, ड्रग शराब शिक्षा कोचिंग नर्सिंग होम स्पा योन मिलावटी नकली खाद्य औषधि राशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि माफियायों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उसका सच जानने के लिए केवल उसके व्यक्तिगत स्टाफ एडीएम एसडीएम आबकारी खनन पंजीयन परिवहन व अन्य सभी विभागों के जिला व संभागीय स्तर के अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर देख ली जाए तो सच समझ में आ जाएगा।

बेशक चवन्नी छाप आठवीं दसवीं पास जिनके पास ना शैक्षिक योग्यता है ना प्रोफेशनल कोई योग्यता है। थोड़ा लिखना पढ़ना क्या सीख गए और पत्रकार बन गए कोई हाकर था कोई मशीन कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लेट बनाने वाला झाड़ू निकालने वाला कर्मचारी था। अपने समाचार पत्र निकालने लग गए तो अधिकारियों के तलवे चाट कर अपने काले कुकर्म को दबाने छुपाने उससे कमाई करने के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। पिल्ले, कोई भी पत्रकार स्नातक कानून की डिग्री अन्य कोई पेशावर शैक्षिक योग्यता धारी ना होने के कारण अपनी रोजी-रोटी चलाने वह सभी अधिकारियों के तलवे चाट कर प्रशंसा कर अपना जीवन यापन कर कर जनता को भ्रमित कर उन हरामखोर जालसाज भेड़ियों को पाल पोस के सांड बनाकर लूटने का खुला आमंत्रण देते हैं क्योंकि कुछ टुकड़े उनकी कमाई से इनको भी मिल जाते हैं।

हर जिले के सबसे बड़े भूमाफिया कलेक्टर उसके अधीनस्थ काम करने वाले एसडीएम एडीएम तहसीलदार राजस्व निरीक्षक पटवारी से लेकर, पंचायतों, परिषदों पालिकाओं, निगमों के सरपंचों से लेकर मुख्य कार्य पालन अधिकारी निगमायुक्त तक सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू कॉलोनी माफियाओं को पालने वाले, मोटा पैसा लेकर अवैध कॉलोनियों को काटने बनाने में रहवासियों से लेकर कॉलोनाइजर्स तक से मोटा पैसा वे अवैध कालोनियां खड़ी करवाते हैं। कालोनियां खड़ी हो जाती है किसी को नहीं दिखती पर खड़ी करने के बाद वह कॉलोनी का भू माफिया कॉलोनी माफिया जिनको प्लाट बैठे थे उनसे नियमित वसूली करने के साथ वह सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी पंच सरपंच व पार्षद विधायक सांसद नेतागिरी, समाचार पत्र वालों पत्रकारों के लिए स्थाई कमाई करते हैं। फिर वैधानिक करने का षड्यंत्र करने के नाम नीचे से ऊपर तक मोटी कमाई की जाती है। अभी भी चुनावी साल में 2-5 करोड़ से लेकर 50 करोड तक की मोटी वसूली कर वैधानिक करने का पाखंड किया जा रहा है। जब तक भूमि भवन की कीमतें सैकड़ों गुना बढ़ चुके हैं।

चुनावी वोटों के लिए एक तरफ ग्रामीणों, अतिक्रमणकारियों, आदिवासियों को पट्टे बांटने का लालच देकर, भू, कॉलोनी, वन कटाई खुदाई सफाई माफियाओं नेताओं, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को सक्रिय कर वन, सरकारी, पशुओं की सरकारी चरनोई की भूमि, नदी, तालाब, नहरें, बांध के जलभराव व संग्रहण क्षेत्रों पर, रेलवे, सड़कें, निगम पालिकाओं पंचायतों, कृषि उद्यानिकी आदि की भूमि पर कब्जे करवा कर पट्टे बांटने, कॉलोनी खड़ी करने झुग्गी बस्ती बसवाने, भू माफियाओं कॉलोनी, खनन, वन कटाई, सफाई के माफियाओं को पालो, पोषो, संरक्षण का षड्यंत्र करो। मोटा चंदा, पैसा वसूल करो अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनी बनाओ। ऐसे नेताओं माफियाओं को संरक्षण देकर पार्षद विधायक सांसद का टिकट बांटो। तो दूसरी तरफ वन अमले, राजस्व, निगम, पालिकाओं, पुलिस लोक निर्माण जल संसाधन, नर्मदा घाटी, गृह निर्माण मंडल के विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाओ, डराओ और सक्रिय करो, कि सरकारी भूमि पर, नदी नालों, तालाबों, नहरों, बांधों, सड़कों नजूल आदि के अतिक्रमण को हटाने के लिए कहो, न हो पाने पर उनको कारण बताओ पत्र दो, निलंबन करो। तो हरामखोर सूअर सत्ताधीशों सारे खेल तुम ही करो। दिग्गी दानव के 93 से 2003 तक के शासनकाल में उसके खास चार चाटुकार चांडाल सुधी रंजन मोहंती, इकबाल सिंह बैंस, आर के अरोरा आदि थे। जिसमें एक यह इकबाल सिंह बैंस जो लगभग पिछले 30 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा सारे प्रदेश के लगभग 100 से ज्यादा विभागों में डकैती डालने के साथ प्रदेश की संपत्तियां निगम सहकारी संस्थाओं साल भर में एक लाख करोड़ की लूट का हिस्से व राजदार भी है। जो अभी भी मध्य प्रदेश के घोर भ्रष्ट जालसाज डकैत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी चांडाल चौकड़ी का मुख्य राजदार डकैत है। इसमें मनीष सिंह, एसएन मिश्रा, मनीष रस्तोगी जिसकी पत्नी दीपाली रस्तोगी पिछले 6 साल से सबसे कमाई की प्रधान सचिव पंजीयन आबकारी, वाणिज्य कर की बैठाई गई है। तीनों की सबसे ज्यादा मोटी कमाई इंदौर से ही होती है।

स्वाभाविक है पुराने राजदार डकैत को ही संभाला जाए अन्यथा नए मुख्य सचिव को बनाने में नया मुख्य डकैत उसकी डकैती में साझेदारी करेगा। इसलिए नया मुख्य डकैत सचिव नहीं बनाया जा रहा। जितने ज्यादा डकैत होंगे उतने राज बंटेंगे और उतने ज्यादा लूट के हिस्से भी करने पड़ेंगे।

इसलिए पुराने वाले से ही सेवा अवधि का विस्तार देकर काम चलाया जा रहा।

इकबाल सिंह बैंस पिछले 30 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर दिग्गी दानव व शिवराज का मुख्य दल्ला व डकैत बनकर बैठा हुआ है।

दूसरी तरफ केरवा डैम और कालिया सोत नदी के किनारे प्रदेश के सभी दिग्गज भ्रष्ट जालसाज डकैत भारतीय प्रताणना सेवा, IAS भारतीय अपराध संरक्षण सेवा, INDIAN (Crime) Protection Services इंडियन (क्राइम) प्रोटक्शन सर्विसेज, ध्हए भारतीय वन (लूटो खाओ) सेवा अधिकारियों, के साथ बड़े मंत्रियों के बंगले और कॉलोनियां ही हैं। जिसमें इकबाल सिंह बैंस सुधी रंजन मोहंती आदि अनेकों उसी के पड़ोसी पड़ोसी और सुरक्षा अधिकारी हैं इसलिए वह डकैत दल्ला सूअर और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सामने क्या खाक जवाब देगा और क्यों जवाब देगा क्या बिगाड़ लेंगे ये हरित प्राधिकरण वाले वह तो वैसे भी सेवा निर्वृत्त हो चुका है बिस्तार पर चल रहा हैअपने साथियों के खिलाफ क्यों और कैसे बोलेगा? इन्हें जनता का वर्तमान व भविष्य सब से कोई मतलब नहीं।

लेख लंबा है पर सच के बाल का सौ वां हिस्सा भी नहीं। सभी घोर भ्रष्ट जालसाज मक्कार डकैत लुटेरे भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारियों को सबसे ज्यादा डर सत्र एवं जिला न्यायालयों से लगता है। यह सब कुछ करेंगे परंतु जिला एवं सत्र न्यायालय में कभी नहीं घुसेंगे। जबकि वहां के न्यायधीश इनका कानूनों का पाठ पढ़ा कर स्वागत करने के लिए सदा बेताब रहते हैं। और औकात हो तो सच को पढ़कर मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें ताकि मैं इनकी सच्चाई ओ का और पुलिंदा न्यायालय में रखकर पूरे देश के सभी भारतीय प्रताणना सेवा अधिकारियों की सच्चाई ना केवल न्यायालयों में बल्कि जनता और देश दुनिया के सामने लाकर रखइनके सारे विदेशों में पड़े खातों संपत्तियों की जांच के लिए भी न्यायालयों को कह व लिख सकूं।

साप्ताहिक समय माया

गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मोबाइल कंपनियां सभी उपयोगकर्ताओं का हर तरह से करती घोर शोषण

(समय माया)

इंटरनेट के माध्यम से बेशक जनता को संचार साधनों की सुविधाएं तो अवश्य मिली। इसके विकास के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स लेकर, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी साइटों ने जनता को अपनी मोटी कमाई के लिए भ्रमित करना अपना व्यवसाय फैलाने से लेकर इन हरामखोर जालसाज चांडालों के साथ हर देश की सरकारों ने मोबाइल ऐप बनाने वालों ने मोबाइल उत्पादन कंपनियों जिसमें सैमसंग, चीनी कंपनियां विवो, एम आई, अप्पो, माइक्रोमैक्स, व अन्य सभी ने उपयोगकर्ताओं का हर तरह से घोर शोषण भी करती हैं। उनकी बातचीत से लेकर, संदेशों, वीडियो चैटिंग, संपर्कों की सूची मोबाइल पड़ा सारा डाटा देखना, जांचना, उसका व्यवसायिक दुरुपयोग भी करती हैं। गूगल, फेसबुक व्हाट्सएप ने भारत की भेडिया झुंड पार्टी के इशारे पर, इन हरामखोर ने संदेशों को उड़ाने, वीडियो, उड़ाने, वीडियो की कटिंग, एडिटिंग करने, उसमें बदलाव करने अपने विरूद्ध चल रहे समाचारों को उड़ाने, अपने झूठ को भी बढ़ा चढ़ा कर सच बताने, अपनी लूट, पाखंड, भ्रष्टाचार, देश की बर्बादी, सार्वजनिक संपत्तियों की नीलामी, जनता को लूटना, डराना, धमकाना, निचोड़ना शुरू कर दिया। इसके बारे में मैं पिछले 7 साल से लगातार लिख रहा हूं। और अब हर सच सामने आने लगा है। वैसे तो घोर पाखंडी भुखमरे मोदी ने चीन के 20 साल तक बहुत तलुवे चाटे। 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए 5-5 साल प्रधानमंत्री रहते हुए 4, कुल 9 चक्कर चीन के लगाए उसकी सारी कंपनियों को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पहले पूरे गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए चीनी कंपनियों को खड़ा कर दिया और प्रधानमंत्री रहते हुए फिर पूरे देश में बदले में गुजरात को 15 साल तक और बाद में पूरे देश के उद्योग धंधे व्यवसायियों को बर्बाद करता रहा। स्वाभाविक था चीन के तलवे चाटने से चीनी कंपनियों को यहां तांडव करने की पूरी छूट मिली और उसने जो मोबाइल उत्पादन कंपनियां भारत में लगाई जिसमें विवो, एम आई, ओप्पो, माइक्रोमैक्स व अन्य कंपनियां उत्पादन भारत में करती रही पर हर मोबाइल खरीददार की सारी जानकारियां चाइना में इकट्ठा होती रही और अभी भी वर्तमान में हो रही है। जब उसने भारत की धरती पर लेह लद्दाख में कब्जा करना शुरू किया। तो मोदी ने उसके 200 चीनी ऐप अवश्य बंद कर दिए पर उत्पादन बंद नहीं

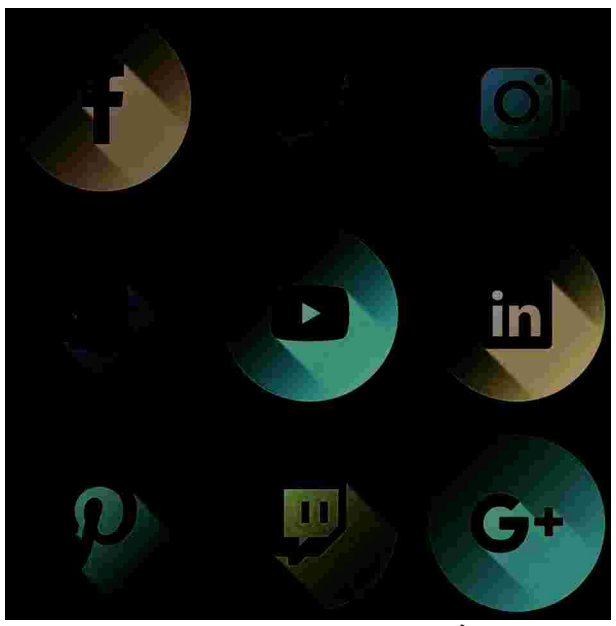

किया स्वभाविक सी बात थी वह सारी कंपनियां आज भी देश की 100 करोड़ चीनी मोबाइल उपयोगकर्ताओं का डाटा चीन में ही इकट्ठा कर रही हैं। हर मोबाइल कंपनी के अपने एप्स उस मोबाइल में डाले रहते हैं। बेशक भारत में गूगल, व्हाट्सएप,फेसबुक पर वे काम करने से नहीं चूकती। परंतु वही बात चीन में किसी भी अमेरिकी कंपनी की सोशल साइट्स और गूगल नहीं चलता। वहां पर उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। इससे चीनी डाटा वैश्विक स्तर पर हैकरों को सार्वजनिक नहीं होता और उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए वहां पर इन के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों से बैंक खातों में डाकाजनी नहीं होती।

पर भारत में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टवीटर को भेड़िया झुंड पार्टी पैसा देकर जनता के हर उपयोगकर्ता की जासूसी करवा कर सारा डाटा इकट्ठा करती हैं। संदेशों को, बदलने, अर्थ का अनर्थ करने, गायब करती, रोकती हैं। बोलने पर लिखने से, बंद करती, रोकती हैं। या संदेशों, वीडियो को बदल देती हैं। बेशक यह सच भारत के किसी भी समाचार पत्र ने नहीं छापा। जबकि मैं यह सच्चाई पिछले 6 सालों से लगातार अपने समाचार पत्र समय माया में छापता रहा हूं।

यह भी धीरे-धीरे सामने आएगा ही। भारत के बैंक खातों में 18-19 में ही लगभग 70 लाख बैंक खातों, डेबिट क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, भीम एप आदि में भारत के अंदर और बाहर से आनलाइन डाके डाले गए। इसी ऑनलाइन गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य ऐप के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया। ना केवल देश वरन दुनिया के हैकरों के लिए डकैती का आसान तरीका बन गया। परंतु भारत सरकार आंतरिक गृह और बाहरी विदेश मंत्रालय इसमें अभी तक कोई हाथ नहीं लगा सका। और भारत की पुलिस हर राज्य की, पहले हर दिन भारत के जिला न्यायालय में उसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पुलिस की जालसाजियों, लूट, डकैती, अपराधीयों की सेवा महिमा का बखान करते हैं। के गुणगान करने की आवश्यकता ही नहीं। वे तो स्वयं खाकी वर्दी के डकैत हैं। इसको जनता समझे।

फेसबुक का मालिक मुस्लिम जुकरबर्ग, टवीटर, गूगल, युटयुब, vimeo, vidyard, dailymotion, metacafe, Billgate of microsoft घोर लालची और बिकाऊ जालसाज षड्यंत्रकारी झूठे और मक्कार हैं। पिछले 6 सालों से भेड़िया झुंड पार्टी से मोटा पैसा खाकर जनवरी 2014 से उसके हिसाब से नाच रहे है इसलिए फरवरी 2014 को जब मैंने देखा कि यह हरामखोर जालसाज सूकर षड्यंत्रकारी झूठे और मक्कार मोदी की सच्चाईयों को तो अपलोड भी नहीं होने देते। परंतु उसके विपरीत मोदी के फैलाए हुए झूठ और पाखंड को आपकी फेसबुक के पेज पर लाकर चिपका देता है और बार-बार बेबस करता है कि इसके ऊपर आप पसंद दें और अच्छी टिप्पणी करें। तब से लेकर अभी तक यह अमेरिकी संकर मुस्लिम जुकर, पैसे के लिए यह सब कुछ कर रहा है। नफरत भरे संदेशों को भाजपा के चलने देता है। पर अन्य लोगो द्वारा मोदी की सच्चाई पूर्ण वीडियो संदेश सब को उड़ा देते है। ये हरामखोर अपनी जालसाजियों के लिए अमेरिकी संसद में अनेकों बार पेशी पर जा चुके है। पर इन धूर्त सूअर मक्कार हरामखोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा पैसा होता है भारत में भी भाजपा के नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर उसकी साइट पर अपलोड होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।

(शेष पेज 10 पर)

देश के असली आका भारतीय प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना अधिकारी

जो लूट सके लूट अंत काल पछतायेगा प्राण जायेंगे छूट

(समय माया)

देश की बर्बादी में इस देश के असली आका भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी घोर अय्याश, बदतमीज, सत्ता के नशे में चूर, मोटी चमड़ी के सूअर, मक्कार, हरामखोर, जालसाज, अपनी मोटी कमाई के लिए आपने देखा इन चांडालों ने देश में कोरोना की महामारी के पाखंड की आड़ में हर तरह से हर कदम अपनी मोटी कमाई कर करोड़ों मासूम नागरिकों का नरसंहार तक करवा दिया। क्योंकि ये मूर्ख नेता मोदी अमित शाह और सारे के सारे राजनीतिज्ञों को नचाने वाली यह सूअर कौम जो है। जिसने भूखे भेड़ियों को दो-दो बार सत्ता मैं ईवीएम के फ्रॉड से जिता कर इसीलिए पहुंचा दिया। ताकि उनकी आड़ में देश की सारी संपत्तियों को अपना मोटा धन जमकर बेचकर विदेशों में अपनी सल्तनत खड़ी कर लें। 90ई आईएएस अधिकारियों का विदेशों में पैसा है। पर मंत्रियों संत्रियों, जांच एजेंसियों की औकात नहीं, की उन पर हाथ डालें। यथार्थ में ये अपना मोटा पैसा अंटी कर विदेशों में भेजकर इन सूअर आईएएस या इंडियन एब्यूजिंग सर्विस अधिकारियों ने सारा पूंजी पतियों को सौंपने का षड्यंत्र का माया जाल बुना है। इस हरामखोर कौम को जो जिला पंचायतों से लेकर एडीएम एसडीएम के साथ कलेक्टर कमिश्नर सचिव प्रधान सचिव मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय मैं अजगर की भांति बैठे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे केंद्र व राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्री सब इनकी कठपुतलियां होते हैं जिन्हें ये अपने मोटे फायदे के लिए नचाते कुदाते, फाइलों पर हस्ताक्षर करवा अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं।

इन हरामखोर जालसाजों को लूटने खाने कानून को अपनी रखैल की जागीर समझ उसका दुरुपयोग कर अपनी मौज मस्ती और धन इकट्ठा करने विदेशों में भेजने संपत्तियां खरीदने में इनका कोई सानी नहीं होता। भूखे गिद्ध अक्ल के दुश्मन किसी भी विषय

के विशेषज्ञ नहीं केवल हर जगह कार्य का टेका होते हैं। जिसे आंग्ल भाषा में कहा जाता है। जैक आफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, jack of all trades but master of none.

यह पूंजी पतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों विदेशी संस्थाओं से मोटा धन लेकर देश की बर्बादी में 75 साल से जुटे हुए हैं। यथार्थ में चारों तरफ इन्हीं का तांडव है।सारी कीमतें बढ़ाने महंगाई बढ़ाने में जनता व देश को बर्बाद करने, देश की संपत्तियों को बेचने उद्योग धंधों को चौपट करने अमेरिका और चीन की गुलामी करने में और उन को लाभ पहुंचाने में इन्हीं चांडालों का मकड़जाल है। जनता इस को समझे। बेशक जनता के द्वारा ईवीएम के फर्जी चुनावों में लोकतंत्र में चुने हुए नेता सरकार चलाते व हांकते दिखते हैं। पर असली खिलाड़ी यह हरामखोर चांडाल भारतीय प्रताणना सेवा की महा धूर्त और मक्कार कौम होती है।

वर्तमान में कार्यरत जिलों के शासकीय कलेक्टर जो अंग्रेजो के समय राजस्व कलेक्टिंग एजेंट हुआ करते थे, आजादी के बाद हरामखोर जालसाजों ने देखा, कि एक अकेला नेहरू कहां-कहां और क्या-क्या हाथ लगा लेगा, इस अंग्रेजी कलेक्टिंग एजेंट ने अपने आप कोदेश की सत्ता से जिले का मालिक बना दिया। सारे कानून सारी सारी व्यवस्थाओं सारे विभागों का वह मालिक बन गया। इन हरामखोर चांडालों की जितने भी कलेक्टर सब भू माफियाओं कॉलोनी माफियाओं खनन माफियाओं के साथ चवन्नी छाप अखिल के नेताओं के वसूली एजेंट हैं।

इन सबके केवल 2 साल की कॉल रिकॉर्डिंग निकालो कितने इमानदार और कितने देशभक्त और कितने व कैसे कानूनों की धज्जियां बिखेरते हैं। चुरकटो की एक-एक काम की व्याख्या कर लो इनकी असली औकात समझ में आ जाएगी। पूरी नौकरी की जिंदगी में अगर इमानदारी से न्याय हो, तो इनके हर अपराधों के लिए 2-5 हजार साल की सजा भी कम पड़ जाएगी। मालवा मिल व अन्य मिलो की जमीन के मामले में, जमीनों पर अरबों रुपए हजम करने, पट्टे निरस्त कर दिये। वह जमीन राजाओं की मिलों के लिए दी गई थी। जब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। पट्टे नहीं हुआ करते थे। तुम्हारा नगर निगम 1956 में अस्तित्व में आया। जो जमीन राजाओं की थी उसको बांटने उसके पट्टे निरस्त करने का कोई अधिकार आपके पास नहीं था। पर करोड़ों रुपए की कमाई की लार टपक रही है। इसी के तो जादूगर है। इसलिए मिल के मजदूरों का हक खत्म कर दो बड़े पूंजीपतियों कॉलोनी वासियों बिल्डिंग माफियाओं को जमीन बेचकर मोटा पैसा कमाने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग कर पट्टे निरस्त कर दिए पर पट्टे आपने दिए थे जो निरस्त कर दिए जो आपने दिया ही नहीं। उसको निरस्त कैसे कर सकते हैं।

(शेष पेज 11 पर)

www.samaymaya.com की साइट से समाचार पत्र की पीडीएफ डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेज सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं क्यू-3, एलआईजी कॉलोनी, गुरुद्वारे के पीछे, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- मोबा. 94251 25569, 94795 35569